नई दिल्ली
बुधवार
16 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 13
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

बिहार कैबिनेट के 17 प्रस्तावों पर मुहर, गयाजी...पेज-05

DELHIN/2014/58158

टी20: संजू-अभिषेक की तूफानी पारी से भारत ने...पेज-06

एक नजर

दिल्ली का नाम 'इंद्रप्रस्थ' करने की मांग, गृह मंत्री को पत्र

नई दिल्ली,एजेंसी। इंद्रप्रस्थ पुनर्जागरण न्यास ने दिल्ली की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और राष्ट्रीय राजधानी का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' किए जाने की मांग की है। न्यास के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर इस संबंध में गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का प्रमुख केंद्र रही है तथा महाभारत काल से इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जोड़ा जाता है। न्यास ने दिल्ली के प्राचीन इतिहास, हिन्दू शासकों और उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार को और अधिक महत्व देने की आवश्यकता जताई। न्यास ने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक बजट के उपयोग की समीक्षा, इंद्रप्रस्थ तथा प्राचीन विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष योजना और इंद्रप्रस्थ की ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए अभियान चलाने की मांग की है। सुरेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि किसी स्थान का नाम उसकी ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किए जाने से देश की प्राचीन विरासत को सम्मान मिलेगा और लोगों का अपनी सांस्कृतिक जड़ों से संबंध मजबूत होगा।

ईडी का दायरा बढ़ेगा, स्वीकृत पदों में 60 प्रतिशत वृद्धि

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभाग के लंबे समय से लंबित कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उसके स्वीकृत पदों में 60 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस पुनर्गठन के बाद ईडी की स्वीकृत पद संख्या 2,029 से बढ़कर 3,256 हो जाएगी। ईडी ने बेंगलुरु स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में 14 और 15 सितंबर को आयोजित 36वें त्रैमासिक क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्मेलन (क्यूसीजेओ) के बाद जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। सम्मेलन की अध्यक्षता ईडी के निदेशक ने की, जिसमें मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ईडी के अनुसार, कैडर पुनर्गठन के तहत ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े 50 जोन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पांच समर्पित जोन बनाए जाएंगे। निदेशालय की कार्य इकाइयों की संख्या 131 से बढ़ाकर 241 की जाएगी। इस व्यवस्था को 01 जनवरी 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन में ईडी निदेशक ने अधिकारियों को आर्थिक अपराधों, बैंक धोखाधड़ी, बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से जुड़े मामलों और साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और मुकदमों में दोषसिद्धि बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र कम-से-कम दस महत्वपूर्ण मामलों की पहचान कर उनके मुकदमों को छह से आठ महीने के भीतर अंतिम चरण तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों को वास्तविक पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ईडी ने बताया कि अब तक 76 मामलों में 73,800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया के तहत चिह्नित या हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क

15 अक्टूबर से लागू

नई दिल्ली,एजेंसी। सरकार ने यूपीआई के जरिये 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क तय किया है जो 15 अक्टूबर से लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार शाम एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि व्यक्तिगत यूपीआई खातों से मर्चेंट खातों में भुगतान पर 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। अधिकतम एमडीआर 300 रुपये होगा।

अनिवार्य सेवाओं जैसे रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि क्षेत्र में बीज, खाद आदि के लिए पांच रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का शुल्क तय किया गया है। पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन जैसे म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति और स्टॉक ब्रोकर और डीलरों के लिए एमडीआर की दर 0.02 प्रतिशत तय की गई है। इसमें भी अधिकतम शुल्क 300 रुपये तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत से व्यक्तिगत यूपीआई खातों में लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यूपीआई से हर महीने एक लाख रुपये तक का लेनदेन करने वाले छोटे व्यापारियों को भी एमडीआर के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले, सरकार ने सोमवार रात एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले ट्राजेक्शन और 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यूपीआई पर एमडीआर लगाने से प्राप्त राशि का बंटवारा यूपीआई अवसंरचना में शामिल सभी साझेदारों के बीच किया जायेगा। इसमें बैंक और यूपीआई ऐप देने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि यूपीआई से होने वाले 96 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये या इससे से कम मूल्य के होते हैं और इसलिए ये शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे।

राहुल गांधी का आरोप- सरकार ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के दो हजार रुपये तक के यूपीआई के जरिए भुगतान को निःशुल्क बनाए रखने की अधिसूचना के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुपचाप दो हजार से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे लेनदेन कुल संख्या का करीब पांच फीसदी हैं, लेकिन इनका कुल लेनदेन मूल्य में हिस्सा करीब 65 फीसदी है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि यूपीआई भुगतान पर सरकार ने कहा कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि दुकानदारों पर शुल्क लगाया जाता है तो उसका बोझ अंततः कहां जाएगा।

यह लागत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल होकर ग्राहकों की जेब पर पड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां लंबे समय से भारत की शून्य एमडीआर नीति का विरोध करती रही हैं और अब सरकार उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल रही है। राहुल गांधी ने इसे अमेरिकी दबाव से जोड़ते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सरकार के इस संभावित बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपीआई को मुफ्त रखने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का असर छोटे और बड़े व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल दो हजार रुपये से अधिक के सभी व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाए जाने का अंतिम निर्णय घोषित नहीं हुआ है।

राजधानी में इस साल अब तक 179 दिन साफ हवा दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 सितंबर के बीच 179 साफ हवा के दिन दर्ज किए गए हैं, जो शहर की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दिल्ली में 172 स्वच्छ वायु दिवस दर्ज किए गए थे, जबकि 2016 में यह संख्या महज 94 दिन थी। 2016 में 94 दिनों से बढ़कर 2026 में 179 साफ हवा के दिन दर्ज होना 85 दिनों का सुधार दर्शाता है।

इस उपलब्धि पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में स्पष्ट और निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। वर्ष 2016 में केवल 94 स्वच्छ वायु दिवसों से बढ़कर इस वर्ष 179 दिन होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए हम इन प्रयासों को और मजबूत करते रहेंगे, ताकि हर मौसम के साथ दिल्ली की हवा और स्वच्छ हो। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को दिल्ली का एक्यूआई 98 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 81 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स द्वारा लगभग 2,279 किलोमीटर सड़कों की सफाई की गई तथा लगभग 170 मीट्रिक टन सड़क की धूल एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए भेजी गई। सरकार के प्रयासों में कचरा प्रबंधन और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है।

पिछले 24 घंटों में लगभग 12,715 मीट्रिक टन कचरा निस्तारित किया गया और वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित उल्लंघनों के लिए 4,976 चालान जारी किए गए। इसी अवधि में लगभग 2,113 मीट्रिक टन एसएक्सडी (निर्माण एवं मालवा) भी हटाया गया। शहर के एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रयासों के तहत भलस्वा, गाजीपुर और ओखला नगर निगम के ठोस कचरा डंपिंग स्थलों पर बायोमाइनिंग के माध्यम से लगभग 19,212 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट (पुराने संचित कचरे) का प्रसंस्करण किया गया।

मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाना पाकिस्तान की खोखली कवायद: भारत

नई दिल्ली,एजेंसी। विदेश मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाने के पाकिस्तान के फैसले को खोखली कवायद बताया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को केवल घोषणाएं करने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वास्तविक और प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।

पाकिस्तान ने अपनी संघीय जांच एजेंसी की रेड बुक में मसूद अजहर पर इनाम 50 लाख पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये किया है। यह इनाम साल 2021 में 50 लाख रुपये था। उन्होंने कहा, 'आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश द्वारा इस तरह की झूठी घोषणाएँ करना-हम सभी जानते हैं कि ये कितनी खोखली हैं। पाकिस्तान को ऐसी घोषणाएँ करने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्रोतों का मानना है कि अजहर पाकिस्तान में है। वहीं, पाकिस्तान का दावा है कि वह अफगानिस्तान भाग गया है। अजहर का नाम साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले समेत कई हमलों से जुड़ा रहा है। माना जा रहा है कि इनाम की राशि बढ़ाने का फैसला अक्टूबर 2026 में होने वाली एफएटीएफ की पूर्ण बैठक से पहले पाकिस्तान की अनुपालन छवि मजबूत करने की कोशिश है।

बिहार में बाढ़ की तबाही पर राहुल, खरगे और प्रियंका ने जताया दुख

नई दिल्ली। बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने की अपील की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उन्होंने आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने की अपील की। राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता से चलाने तथा प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने की अपेक्षा जताई।

वर्षों से लंबित किशाऊ बांध परियोजना ने पकड़ी गति, नई दिल्ली में छह राज्यों के बीच हुआ अहम समझौता

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर छह राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना वर्षों से लंबित इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित संबंधित राज्यों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने बताया कि रेणुका जी, लखवार और किशाऊ इन तीनों परियोजनाओं से हरियाणा के पानी का शेयर लगभग 1143 एमसीएम होगा। इन तीनों परियोजनाओं से कुल 2676 क्यूसेक पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसमें से 1280 क्यूसेक पानी हरियाणा के हिस्से में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना में हरियाणा के पानी का हिस्सा 48 प्रतिशत है। ऐसे में यमुना में पानी की उपलब्धता बढ़ने से हरियाणा को इसका सीधा लाभ मिलेगा। किशाऊ परियोजना के साथ-साथ रेणुका जी और लखवार परियोजनाएं भी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर पहले से ही निर्माण कार्य चल रहा है और अब जल्द ही किशाऊ परियोजना पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। बढ़ती आबादी और विकास के साथ आने वाले समय में पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे में इन परियोजनाओं से बढ़ने वाली पानी की उपलब्धता हरियाणा की वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

कैबिनेट फैसलाः स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए नवीन राज्य नीति-2026 को मंजूरी

लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सेहत (फिटनेस) को बेहतर करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भीतर 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन' (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन-एटीएस) स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। अब गाड़ियों की जांच मशीनों से की जाएगी, जिससे सटीक रिपोर्ट मिलेगी। इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए सरकार ने 2 अगस्त 2023 के पुराने सरकारी आदेश को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक नई नीति 'राज्य नीति-2026' को पास किया है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में

तीन एटीएस सेंटर खोले जा सकते हैं। हर सेंटर पर 24 हजार गाड़ियों तक जांच की जाएगी। वहीं पूर्व में सेंटर के लिए 2.5 एकड़ जमीन की शर्तों में भी छूट दी गई है, अब यह 1 एकड़ कर दिया गया है। वहीं एटीएस सेंटर खोलने के लिए पहले 6 करोड़ रुपये की नेटवर्थ की अनिवार्यता थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके अलावा इन सेंटरों को सुचारु रूप से संचालित होने के लिए 6 महीने तक कार्रवाई में भी छूट मिलेगी। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की 23 सितंबर 2021, 31 अक्टूबर 2022, 14 मार्च 2024 और 8 मई 2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में अध्याय-11 के तहत स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) का विनियमन एवं नियंत्रण जोड़ा गया है।

दिल्ली के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू

नई दिल्ली,एजेंसी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और आधुनिक तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। यह सुविधा नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि वाणिज्यिक पहल के तहत शुरू की गई इस सुविधा के माध्यम से यात्री अपने सामान को अस्थायी रूप से सुरक्षित रख सकेंगे। डिजिटल लॉकर में डिजिटल एवं ओटीपी आधारित एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इससे यात्री ट्रेन के बीच लंबी प्रतीक्षा अवधि या स्टेशन से बाहर भ्रमण के दौरान अपना भारी सामान सुरक्षित रूप से लॉकर में रख सकते हैं।

यह सुविधा विशेष रूप से पर्यटकों, ट्रेनों के बीच लंबी प्रतीक्षा अवधि वाले यात्रियों

और भारी सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी होगी। यात्री अपनी आवश्यकता के अनुसार मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज आकार के लॉकर का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सामान जमा करने के लिए यात्री को लॉकर मशीन पर 'स्टार्ट' विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद ओटीपी सत्यापन, लॉकर के आकार और समयावधि का चयन तथा डिजिटल भुगतान करने के बाद सामान लॉकर में रखकर उसे बंद करना होगा। सामान वापस लेने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित करना होगा। इसके बाद 'रिलीज' विकल्प चुनकर लॉकर खोला जा सकेगा और सामान निकालने के बाद लॉकर बंद करना होगा। भुगतान के लिए गूगल पे, पेटीएम, फोनपे समेत अन्य डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के नीचे मेन हॉल में उपलब्ध है।

वहीं, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा मुख्य प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियों के बगल में स्थित है। दोनों स्टेशनों पर यह सुविधा 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के अनुसार, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर डिजिटल लॉकर सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, सुगमता और उपलब्ध स्थान के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए लॉकर लगाए जा रहे हैं। रेलवे का कहना है कि यह पहल यात्रियों के यात्रा अनुभव को और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी।

डूसू चुनाव में एनएसयूआई की जीत का दावा, देवेन्द्र यादव बोले- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ होगा मतदान

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के पैनल को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को होने वाले चुनाव में छात्र मौजूदा शिक्षा नीति और भाजपा सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने छात्रों से एनएसयूआई के पैनल 6-4-1-2 को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इससे देशभर में बदलाव का संदेश जाएगा और छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे। देवेन्द्र यादव ने नजफगढ़, चांदनी चौक और नई दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों को संबोधित किया। इन बैठकों का आयोजन संबंधित जिला अध्यक्षों मौहम्मद उस्मान, महेन्द्र मंगला और राजेश यादव की ओर से किया गया। बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, एनएसयूआई और डूसू के पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों, जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों तथा विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। देवेन्द्र यादव ने कहा कि एनएसयूआई से जुड़े छात्र प्रत्येक महाविद्यालय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क करें और उन्हें मौजूदा शिक्षा नीति से जुड़ी समस्याओं तथा भाजपा सरकार की नीतियों के कारण छात्रों के सामने पैदा हुई

चुनौतियों से अवगत कराएं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की ओर से छात्रों के अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चुनाव के अंतिम चरण में पूरी ताकत के साथ छात्रों तक पहुंचना चाहिए, ताकि संगठन का पैनल डूसू चुनाव में एकतरफा जीत हासिल कर सके।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनाव जिताने के लिए हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा कथित तौर पर डूसू चुनाव में भी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। देवेन्द्र यादव ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से ऐसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान पूरी सक्रियता के साथ काम करना होगा और छात्रों के मतदान के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। ऐसे में डूसू चुनाव का परिणाम केवल विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका संदेश देशभर में जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एनएसयूआई प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी मेहनत करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि डूसू में एनएसयूआई की जीत छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाने और देशभर में बदलाव का संदेश देने का माध्यम बनेगी। देवेन्द्र यादव ने कहा कि एनएसयूआई 'जवाबदेह दिल्ली विश्वविद्यालय- जवाबदेह डूसू' घोषणा पत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। घोषणा पत्र में 19 वादों के माध्यम से शिक्षा, शुल्क, छात्रावास, परिवहन, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, खेल, छात्रवृत्ति और रोजगार जैसे विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की समस्याओं पर सीधे संवाद करना चाहिए। सस्ते छात्रावास, मेट्रो रियायती यात्रा पास की लंबित मांग, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और महिला सुरक्षा जैसे विषयों को प्रमुखता से विद्यार्थियों के बीच उठाने की जरूरत है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि एनएसयूआई का पैनल चुनाव जीतता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के छात्रों की अधिकतर समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। बैठकों में दिल्ली के प्रभारी काजी

दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस की नई टीम गठित, 51 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल का गठन

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस की एडवाइजरी काउंसिल, नई प्रदेश कमेटी एवं जिला अध्यक्षों का गठन किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम के गठन से संगठन दिल्ली के प्रत्येक जिले, ब्लॉक और बूथ स्तर पर अधिक सक्रियता से काम करेगा। देवेन्द्र यादव ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद के निर्देशन में दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया है। 12 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति अधिसूचना के तहत दिल्ली प्रदेश ओबीसी विभाग के चेयरमैन राजीव वर्मा के नेतृत्व में 51 एडवाइजरी काउंसिल सदस्यों, 21 प्रदेश उपाध्यक्षों, 23 प्रदेश महासचिवों, 24 प्रदेश सचिवों एवं 13 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि ओबीसी चेयरमैन राजीव वर्मा संगठन को मजबूत बनाने तथा राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के संकल्प को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नई टीम के माध्यम से दिल्ली में ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समानता और न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही, 'जितनी आबादी, उतना हक' की आवाज को दिल्ली के प्रत्येक जिले, ब्लॉक और बूथ तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन राजीव वर्मा ने कहा कि 'जितनी आबादी, उतना हक' केवल नारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का हमारा संकल्प है। दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस इस संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस को एक मजबूत, सक्रिय और संघर्षशील संगठन के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन सामाजिक न्याय की लड़ाई को जमीनी स्तर तक पहुंचाने तथा ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करेगा।

वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा की मांग के लिए बस ड्राइवरों ने की हड़ताल

नई दिल्ली। डीटीसी और परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों के ड्राइवरों ने मंगलवार सुबह हड़ताल कर दी। वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा, सालाना बोनस और ओवर टाइम का भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर ड्राइवर काम बंद कर सड़कों पर उतर आए। बुराड़ी, दिलशाद गार्डन, केशोपुर, ग्रेटर कैलाश, झिलमिल समेत अधिकांश डिपो में हड़ताल हो जाने और बसों के सड़कों पर न निकलने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें मेट्रो, ऑटो और अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों से यात्रा करनी पड़ी। ड्राइवरों का कहना है कि 10-15 साल का अनुभव होने के बावजूद उन्हें अकुशल श्रमिकों की तरह दैनिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें प्रतिदिन 862 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जबकि इसी काम के लिए डीटीसी के स्थायी ड्राइवरों को 50-60 हजार से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है।

उनका कहना है कि इन बसों के ड्राइवरों को न तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है और न ही ओवर टाइम का भुगतान किया जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 10 से 11 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर बस ऑपरेटर्स और डिपो के अधिकारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार से हड़ताल का फैसला लिया गया। दिल्ली के कुछ डिपो में सुबह की शिफ्ट में ड्राइवर बसों को लेकर निकल गए थे, लेकिन दोपहर तक सभी डिपो में हड़ताल का संदेश पहुंच गया।

जामिया के छात्रों ने VMAC 2026 में शानदार प्रदर्शन कर जीते 21 हजार

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लॉ फैकल्टी के छात्रों ने वर्चुअल मेडिएशन एडवोकेसी कॉम्पिटिशन (VMAC) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में 60 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें जामिया की टीम ने मध्यस्थता, एडवोकेसी, नेगोशिएशन और फैसिलिटेशन में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जामिया का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम में तृतीय वर्ष के छात्र अज़ीज़ उमर, चतुर्थ वर्ष की छात्रा सैयदा युसरा और तृतीय वर्ष की छात्रा सारा अज़फ़र शामिल रहीं। टीम को उसके सराहनीय प्रदर्शन के लिए 20,000 की VMAC स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, टीम ने स्पेशल अवार्ड्स कैटेगरी में पांचवां स्थान हासिल किया, जिसके लिए 1,000 का पुरस्कार मिला। इस प्रकार टीम को कुल 21,000 की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई।

प्रतियोगिता के दौरान टीम ने मेडिएशन एडवोकेसी परीक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और

100 प्रतिशत का कुल स्कोर हासिल कर परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। यह उपलब्धि छात्रों की मध्यस्थता संबंधी कौशल, तैयारी और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है। लॉ फैकल्टी ने छात्रों की इस उपलब्धि को उनके समर्पण, मेहनत और ष्ठक्रमें विशेषज्ञता हासिल करने की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। फैकल्टी का कहना है कि इस प्रदर्शन से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ष्ठक्र प्रतियोगिताओं में बढ़ती उपस्थिति को और मजबूती मिली है। लॉ फैकल्टी ने डीन प्रो. (डॉ.) गुलाम यज़दानी और फैकल्टी कन्वेनर डॉ. अलीशा खातून के निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उनके मार्गदर्शन से छात्रों को ष्ठक्रप्रतियोगिताओं में भाग लेने और अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर प्राप्त हुए। टीम ने प्रतियोगिता के दौरान समर्पित मेंटरशिप, बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए सुश्री इसरा मुख्तार और सुश्री खदीजा मिर्ज़ा का भी आभार जताया। लॉ फैकल्टी ने अज़ीज़ उमर, सैयदा युसरा और सारा अज़फ़र को इस सराहनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।

भाजपा ने विवाद पर विधायक व मंडल अध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। भाजपा के लिए मुंडका विधायक और कंझावला मंडल अध्यक्ष के बीच विवाद ने मुसीबत खड़ी कर दी है। इसे लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर निशाना साध रहा है। इसे देखते हुए भाजपा ने दोनों को नोटिस देकर बुधवार तक प्रदेश अनुशासन समिति के समक्ष स्पष्टीकरण सौंपने को कहा है। इन दोनों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंडका विधायक गजेंद्र दराल और कंझावला मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार के बीच विवाद सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वीडियो में मारपीट व आपत्तिजनक शब्दों का आरोप लगाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी की ओर से प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी विष्णु मित्तल ने नोटिस जारी कर दोनों से घटना पर लिखित जवाब मांगा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व इस घटना को लेकर काफी संजीदा है। क्षेत्रीय सांसद और जिलाध्यक्ष से बातचीत के बाद विधायक गजेंद्र दराल और मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार को अलग-अलग नोटिस देकर बुधवार दोपहर 3 बजे तक प्रदेश अनुशासन समिति के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही तय होगी। मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की पूरी स्वतंत्रता है।

दिल्ली की 53 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए 427 सहायक पद मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में स्थापित 53 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के प्रभावी संचालन के लिए 427 सहायक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर रीडर,वरिष्ठ न्यायिक सहायक, आशुलिपिक, अहलमद, चालक और मल्टी टास्किंग स्टाफ शामिल होंगे। इन पदों के सृजन से 53 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। स्वीकृत पदों में 58 रीडर या वरिष्ठ न्यायिक सहायक, 58 वरिष्ठ निजी सहायक (आशुलिपिक), 58 निजी सहायक (आशुलिपिक), 58 अहलमद या न्यायिक सहायक, 58 सहायक अहलमद या कनिष्ठ न्यायिक सहायक, 20 स्टाफ कार चालक और 117 मल्टी टास्किंग स्टाफ शामिल हैं। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के लिए 10 फीसदी अवकाश आरक्षित पद भी शामिल हैं।

प्रस्ताव की प्रशासनिक सुधार विभाग ने कानून विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव से जुड़े वित्तीय भार की समीक्षा की। कुल 37.37 करोड़ रुपये के वित्तीय भार वाले प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दी है। हालांकि, नए पदों को प्रभावी करने से पहले मौजूदा 415 अदालतों में खाली पड़े 243 सहायक पदों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द भरने की शर्त रखी गई है। इसके बाद ही नए पदों को संचालन में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इन 53 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के प्रवेश स्तर के 53 न्यायिक अधिकारियों के पद पहले ही उपराज्यपाल की मंजूरी से सृजित किए जा चुके हैं। अब सहायक कर्मचारियों के पदों को मंजूरी मिलने से इन अदालतों के पूर्ण रूप से संचालन का रास्ता साफ हुआ है।

प्रिंटर देखने के बहाने घर में घुसे हमलावर, महिला पर छह गोलियां बरसाईं

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के नंगली एक्सटेंशन में पत्नी की हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक पति ने पत्नी की हत्या के लिए अपने बचपन के दोस्त को 3.5 लाख रुपये की सुपारी दी। साजिश के तहत दो हमलावर प्रिंटर देखने के बहाने महिला के घर में दाखिल हुए और करीब 40 मिनट बाद उस पर 6 गोलियां चला दीं। हमले में महिला को 3 गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामले में मंगलवार को दोनों हमलावरों दीपक और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, घायल महिला के पति संदीप को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। साजिश में कथित रूप से शामिल उसका बचपन का दोस्त अरविंद अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार, वारदात रविवार सुबह करीब 6 बजे नंगली एक्सटेंशन की गली नंबर-1 में हुई। संदीप ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी संध्या से कहा था कि घर पर 2 लोग प्रिंटर देखने के लिए आएंगे। कुछ देर बाद दीपक और आकाश वहां पहुंचे और प्रिंटर की जांच करने की बात कहकर घर के भीतर प्रवेश कर गए। दोनों करीब 40 मिनट तक घर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रिंटर खोलकर उसकी जांच करने का बहाना किया। जब संध्या उनके लिए पानी लेकर पहुंची, तभी दोनों ने अचानक उस पर गोलियां चला दीं। हमलावरों ने संध्या पर कुल 6 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 गोलियां उसे लगीं। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा और घायल संध्या को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने समय पर उपचार शुरू किया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हमलावरों की पहचान की और मंगलवार को दीपक तथा आकाश को गिरफ्तार कर लिया।

एमसीडी ने 296 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित, महापौर प्रवेश वाही ने दी बधाई

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। महापौर प्रवेश वाही ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम सफाई कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दिल्ली को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। निगम प्रशासन द्वारा जोनल स्क्रीनिंग कमेटियों की संस्तुतियों और संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर 296 सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है।

160 कर्मचारियों को 2006 और 136 को 2008 से लाभ

निगम के अनुसार, नियमितीकरण का लाभ दो श्रेणियों में दिया गया है। 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2000 के बीच सामान्य रूप से कार्यरत 160 दैनिक

वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2006 से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया है। वहीं, 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 के बीच कार्यरत 136 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2008 से नियमित किया गया है। महापौर ने कहा कि नियमितीकरण से संबंधित कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रति अधिक सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध निगम

प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुरूप नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने में योगदान देने वाले प्रत्येक सफाई कर्मचारी का सम्मान और कल्याण निगम की जिम्मेदारी है।

भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए वादे पूरे कर रही: संदीप कपूर

पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल आश्वासन देने का कार्य किया, जबकि निगम में भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है।

स्पाइसजेट की दुबई की दो उड़ानों में काफी देरी होने पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पर एक बार फिर विमान के उड़ान में देरी के कारण यात्रियों ने हंगामा किया और लगातार हो रही देरी को लेकर वह धरना पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के करीब 200 यात्रियों ने सोमवार से दुबई की उनकी उड़ानों का कई बार समय बदले जाने एवं बहुत ज्यादा देरी होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसकी आलोचना की है। यात्रियों की परेशानी, धरना देने सहित कर्मचारियों के यात्रियों के बहस का भी वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने एयरलाइंस से जुड़े अपने खराब अनुभव भी साझा किया। एक वीडियो में यात्री फर्श पर बैठे हैं जबकि एक अन्य वीडियो में एक कर्मचारी यात्रियों से वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है। धीरे धीरे यात्रियों का वीडियो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी वायरल हो गया और लोगों ने इस पर शिकायत भरे कमेंट किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को दुबई के लिए दो उड़ानें -एसजी 5111 और एसजी 5105 - क्रमश: सुबह और शाम को रवाना होने वाली थीं, लेकिन उनके प्रस्थान का समय बदल दिया गया। ऐसे में कई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। थोड़ी थोड़ी देर पर उड़ान के समय में परिवर्तन के कारण यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया। लंबे समय से यात्री चेकइन के लिए टर्मिनल तीन पर इंतजार करते रहे। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली दो उड़ानों में 24 घंटे से ज्यादा की देरी होने से यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा है। एक उड़ान को कल सुबह रवाना होना था, लेकिन वह अभी तक उड़ान नहीं भर सकी थी। दूसरी उड़ान कल रात के लिए निर्धारित थी, वह भी एयरपोर्ट पर ही खड़ी रही। बार-बार उड़ान टलने से यात्री परेशान हो गए और उन्होंने टर्मिनल पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लिखा कि प्रदर्शन के समय तक स्पाइसजेट ने देरी को लेकर सार्वजनिक रूप से विस्तृत कारण नहीं बताया था।

एमसीडी का दिल्लीभर में प्रवर्तन अभियान तेज, 40 विध्वंस कार्रवाई और 16 संपत्तियां सील

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपविधियों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। निगम के सभी 12 जोनों में चलाए गए गहन अभियान के दौरान मंगलवार को 40 विध्वंस कार्रवाई की गईं। इसके अलावा 16 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि भवन मानदंडों और नियमों के उल्लंघन पर 4 विध्वंस आदेश भी पारित किए गए। एमसीडी के अनुसार, भवन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से दिल्लीभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माण तथा भवन मानदंडों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक दिन पहले भी 40 संपत्तियों पर कार्रवाई

निगम ने सोमवार को भी व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया था। इस दौरान दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामलों में 40 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया तथा 8 अन्य संपत्तियों को सील किया गया। एमसीडी का कहना है कि लगातार जारी यह अभियान अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने और वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में निगम के प्रयासों का हिस्सा है।

दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी दिल्ली में प्रमुख कार्रवाई

मंगलवार को चलाए गए अभियान में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रमुख विध्वंस एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

दक्षिण जोन: गौशाला रोड और सतबड़ी में कार्रवाई।

पश्चिम जोन: विशाल एन्क्लेव, हस्तसाल, विकासपुरी एक्सटेंशन और उत्तम नगर में विध्वंस कार्रवाई।

उत्तरी जोन: सब्जी मंडी क्षेत्र में विध्वंस सहित प्रवर्तन कार्रवाई।

पूर्वी जोन: न्यू सीलमपुर, मयूर विहार फेज-1 और पांडव नगर में प्रमुख कार्रवाई।

इसके अलावा एमसीडी के शेष जोनों में भी विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जनसुरक्षा से जुड़े उल्लंघनों पर सख्ती

एमसीडी ने दोहराया कि खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण तथा भवन उपविधियों के उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। निगम का उद्देश्य भवन मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऐसे निर्माणों पर रोक लगाना है, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

दिल्लीभर में पीजी भवनों का सर्वेक्षण जारी

एमसीडी ने अपने निरंतर निरीक्षण अभियान के तहत दिल्लीभर में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासीय भवनों का मैदानी सर्वेक्षण भी शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राजधानी में संचालित पीजी सुविधाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना और लागू भवन मानदंडों तथा नियमों के अनुपालन का आकलन करना है। निगम के अब तक किए गए सर्वेक्षण में लगभग 2,453 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। इन भवनों में करीब 55,000 लोग रह रहे हैं। एमसीडी के अनुसार, सर्वेक्षण के माध्यम से पीजी भवनों की स्थिति, संचालन और भवन नियमों के अनुपालन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।

एक नजर

जिमखाना क्लब के सदस्यों को हाईकोर्ट जाने की अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी। इन सदस्यों ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत क्लब की 27.3 एकड़ जमीन और बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेने और उसके बाद खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इन 11 सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि अभी क्लब का मैनेजमेंट केंद्र सरकार की बनाई एक कमेटी संभाल रही है और वह सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। सिंह ने कहा कि सरकार की बनाई कमेटी ने चुनाव कराने और चुने हुए लोगों को नियंत्रण सौंपने के लिए एनसीएलएटी की तय समय-सीमा से ज्यादा समय ले लिया है और यह क्लब पर कब्जा करने की एक गलत नीयत वाली कोशिश है। उन्होंने कहा कि यहां, लीज देने वाला और लीज लेने वाला, दोनों ही सरकार के नियंत्रण में हैं। इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने विपिन अग्रवाल और क्लब के 10 अन्य सदस्यों की याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें यह छूट दी कि वे या तो दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर करें या फिर खाली कराने की कार्रवाई से जुड़े लंबित मामले में खुद को पक्षकार बनाएं।

लाल किला मैदान में दिव्यांगों को मिलेंगे कृत्रिम अंग

नई दिल्ली। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से 17 सितंबर को लाल किला मैदान में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में जरूरतमंद दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करेंगे। शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, तारा संस्थान तथा एलप्स के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। अर्जुन कुमार के अनुसार शिविर में जापानी तकनीक से निर्मित 3डी मुद्रित मॉड्यूलर कृत्रिम अंग और कैलिपर्स दिए जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन ने बताया कि तारा संस्थान द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच, चश्मों का वितरण और मोतियाबिंद रोगियों को ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि जरूरतमंदों को कानों की मशीन और ट्राईसाइकिल भी वितरित की जाएंगी। कमेटी ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक शिविर की जानकारी पहुंचाकर उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

वाल्मीकि सदन के 145 क्वार्टर खाली करने की सलाह

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने जन सुरक्षा के मद्देनजर वाल्मीकि सदन के 8 आवासीय खंडों में स्थित 145 टाइप-1 क्वार्टरों को खाली करने की सलाह जारी की है। परिषद के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संरचनात्मक आकलन में इन भवनों को आवासीय उपयोग के लिए असुरक्षित और आर्थिक रूप से मरम्मत योग्य नहीं पाया गया। प्रभावित आवासीय खंडों में 1965-66 में निर्मित 3 मंजिला 4 खंड शामिल हैं, जिनमें जी-25 से जी-51, एफ-25 से एफ-51 और एस-25 से एस-51 तक के कुल 81 क्वार्टर हैं। इसके अलावा 1985-86 में निर्मित 4 मंजिला 4 खंडों में ब्लॉक संख्या 1 से 64 तक के 64 क्वार्टर शामिल हैं। परिषद ने भवनों की खराब होती संरचनात्मक स्थिति और संभावित जोखिम को देखते हुए निवासियों से चिह्नित क्वार्टर जल्द से जल्द खाली करने तथा निकासी प्रक्रिया में अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है। एनडीएमसी ने स्पष्ट किया कि यह कदम निवारक और सावधानी के तौर पर उठाया गया है। परिषद ने कहा कि निवासियों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा तकनीकी आकलन और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

गणेश भजन संध्या में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया'

गांधी कॉलोनी। गांधी कॉलोनी स्थित गणेश पार्क में महाराष्ट्र मित्र मंडल की ओर से आयोजित सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव के तहत 14 सितंबर को भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध गायक प्रीतम पोदार ने गणेश भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत 'जय गणेश जय गणेश देवा' से हुई। इसके बाद 'सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में', 'देवा श्री गणेशा', 'मणिहार के भेष बनाया' और मराठी भजन 'आमच्या पप्पांनी गणपती आणला' प्रस्तुत किए गए। भजनों के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ 'गणपति बप्पा मोरया' के जयघोष लगाए। करताल और ढोलक की ताल पर श्रद्धालु गणपति की भक्ति में लीन नजर आए। कार्यक्रम के समापन पर मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र पांचाल, विलास पांचाल, रविन्द्र पांचाल, रमाकांत गुप्ता और अक्षय ने कलाकारों को पारंपरिक फेंटा और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। मंडल पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूत करते हैं।

नौ अक्टूबर से होगा श्री दुर्गा रामलीला का भव्य मंचन, हो रही रिहर्सल

गुरुग्राम। भगवान गणेश के पूजन और धार्मिक विधि-विधान के साथ श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट ने अपनी 61वीं रामलीला के मंचन की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ कर दिया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के बाद रामलीला के सभी स्वरूप कलाकारों का धागा बंधन संस्कार किया गया। धागा बंधन के साथ ही कलाकारों ने भगवान श्रीराम की लीला को श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लिया।

श्री दुर्गा रामलीला कमेटी इस वर्ष अपने 61वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस ऐतिहासिक सफर की रामलीला मंचन को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों और कलाकारों में विशेष उत्साह है। आगामी नौ अक्टूबर से श्री दुर्गा रामलीला का भव्य मंचन शुरू होगा। इसके लिए कलाकारों की नियमित रिहर्सल शुरू हो चुकी है। मंचन को यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। गणेश

चतुर्थी के अवसर पर हुए धागा बंधन के बाद सभी स्वरूप कलाकार दशहरा पर्व तक रामलीला मंचन के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कलाकारों की नियमित रिहर्सल के साथ-साथ संवाद, अभिनय, भाव-भंगिमा, आवाज, सुर-ताल और मंचीय प्रस्तुति की बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर श्री दुर्गा रामलीला कमेटी के प्रधान कपिल सलूजा और सचिव अशोक प्रजापति ने बताया कि 61वें वर्ष के रामलीला मंचन को यादगार बनाने के लिए इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं।

रामलीला स्थल की साज-सज्जा, मंच, टेंट और लाइटिंग को भव्य रूप देने के साथ-साथ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि रामलीला देखने आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कमेटी के प्रेस प्रवक्ता राजकुमार सैनी ने बताया कि रामलीला को भव्यता प्रदान करने के लिए कलाकार पूरी लगन और मेहनत से रिहर्सल में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नए कलाकारों को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा, जिससे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी कलाकार तैयार होते रहें। इस अवसर पर श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, सदस्यगण एवं कलाकार उपस्थित रहे।

पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने तकरीबन तीन साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपित को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी राजा अली अपने एक साथी के साथ हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सिसाना-बिलौचपुर नहर पटरी के पास किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें राजा अली के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपित राजा अली थाना कोतवाली बागपत का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

डूसू चुनाव में सत्य निकेतन हादसे की गूंज, आवास सबसे बड़ा मुद्दा

नई दिल्ली। राजधानी के सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने की घटना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास और पीजी की सुरक्षा का मुद्दा डूसू चुनाव के केंद्र में ला दिया है। डूसू चुनाव के लिए जारी तीनों प्रमुख छात्र संगठनों के घोषणापत्रों में अब सुरक्षित और किफायती छात्र आवास सबसे प्रमुख साझा मुद्दों में शामिल है। सत्य निकेत हादसे में छात्रों की मौत के बाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा और आवास व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और सुरक्षित छात्र आवास की मांग तेज हुई। छात्रों ने पीजी की सुरक्षा जांच, हॉस्टल की कमी दूर करने और किराये के मकानों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। हादसे के बाद यह मुद्दा केवल एक इमारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डीयू में पढ़ने वाले बाहर से आने वाले हजारों छात्रों के सामने रहने की समस्या और महंगे तथा असुरक्षित पीजी के विकल्प का सवाल भी चुनावी बहस में आ गया है। अब स्थिति यह है कि सत्य निकेतन ही नहीं राजधानी के अधिकांश पीजी के छात्रों से मिलने छात्र संगठनों के पदाधिकारी या उसके समर्थक जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अपने घोषणापत्र में नए हॉस्टल बनाने और छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इसके लिए छात्र आवास प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन बनाने का प्रस्ताव है। संगठन ने पीजी और हॉस्टल की सुरक्षा जांच, अग्नि सुरक्षा, सफाई, पेयजल और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं एनएसयूआई ने सुरक्षित आवास के साथ किराये के बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उसके घोषणापत्र में किराया नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और छात्रों के लिए सत्यापित पीजी तथा किराये के आवास की जानकारी उपलब्ध कराने वाला डीयू पोर्टल बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा छात्र आवास की समस्या को मेट्रो रियायती पास, कैंपस सुविधाओं और छात्र कल्याण से भी जोड़ा गया है। आइसा-एसएफआई गठबंधन ने प्रत्येक कॉलेज में कम से कम दो हॉस्टल बनाने की मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से सुरक्षित आवास की पहचान कर छात्रों को किराये में सहायता देने और प्रत्येक कॉलेज तथा प्रमुख विश्वविद्यालय क्षेत्र के दो किलोमीटर दायरे में किराया नियंत्रण कानून लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

योगी सरकार की ग्रीन मोबिलिटी को मिली रफ्तार, ई-बसों का शानदार प्रदर्शन

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रीन मोबिलिटी और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के विजन का असर नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के संचालन प्रतिफल (राजस्व) में लगातार दिखाई दे रहा है। सितंबर माह के प्रथम 13 दिनों में डिपो की 100 ई-बसों ने कुल 2.96 लाख किलोमीटर का परिचालन कर 1.99 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की और 61.75 लाख से अधिक का राजस्व अर्जित किया। इस अवधि में प्रति बस प्रतिदिन परिचालन, यात्री संख्या और आय के आधार पर अगस्त की तुलना में बेहतर औसत दैनिक प्रदर्शन दर्ज किया गया। नोएडा इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन प्रारंभ होने के बाद 20 जून से 13 सितंबर 2026 तक तीनों प्राधिकरणों की ई-बसों ने कुल 15.12 लाख किलोमीटर से अधिक का परिचालन किया। इस दौरान 7.18 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ई-बस सेवा का लाभ उठाया, जिससे कुल 2.24 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया।

नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के अधिकारियों के मुताबिक 20 से 30 जून के 11 दिनों में 100 ई-बसों ने 1.47 लाख किलोमीटर का परिचालन कर 28,053 यात्रियों को सेवा दी और 9.07 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया। जुलाई में

परिचालन बढ़कर 4.79 लाख किलोमीटर, यात्री संख्या 1.50 लाख और राजस्व 47.93 लाख तक पहुंच गया। अगस्त में बसों ने 5.89 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और 3.40 लाख यात्रियों को सेवा दी। इस महीने 1.05 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। सितंबर के प्रथम 13 दिनों में ही 2.96 लाख किलोमीटर परिचालन, 1.99 लाख यात्रियों और 61.75 लाख का राजस्व प्राप्त किया। अगस्त के 190.21 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन के मुकाबले सितंबर में यह बढ़कर 227.78 किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार यात्री प्रति बस प्रतिदिन की संख्या 109.79 से बढ़कर 153.68 और आय प्रति बस प्रतिदिन 3,414.86 से बढ़कर 4,750.20 रुपये हो गई। आय प्रति किलोमीटर भी 17.95 से बढ़कर 20.85 रुपये हो गई है। चारों अवधियों को मिलाकर 20 जून से 13 सितंबर तक कुल 15.12 लाख किलोमीटर से अधिक का परिचालन हुआ, जबकि 7.18 लाख यात्रियों ने ई-बस सेवा का लाभ लिया। इस दौरान कुल 2.24 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2026 में नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन और ई-बसों को हरी झंडी दिखाते हुए एनसीआर में स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया था। उनका विजन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को ग्रीन मोबिलिटी से जोड़ते हुए जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत करना है।

फ्लिपकार्ट शिपमेंट में हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 40 लाख के मोबाइल बरामद

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शिपमेंट में हेराफेरी कर लाखों रुपये का चूना लगाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपये कीमत के 42 ब्रांडेड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बड़ौत निवासी हिमांशु, शामली के बाबरी निवासी अभिषेक और बागपत निवासी अनिल शामिल हैं। गिरोह का सरगना और हब इंचार्ज आशीष चौधरी है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले करीब डेढ़ साल से शिपमेंट में हेराफेरी कर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। आरोपी शिपमेंट की अनलोडिंग के दौरान महंगे मोबाइल फोन पार्सलों से निकाल लेते थे और इस पूरी वारदात को सीसीटीवी कैमरों से बचकर अंजाम देते थे। इसके बाद चोरी किए गए मोबाइलों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में बेच दिया

जाता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में कंपनी को करीब 77 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। बरामद किए गए मोबाइल विभिन्न नामी कंपनियों के हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया है कि यह सारी कार्रवाई बड़ौत क्षेत्राधिकारी अंशु जैन के नेतृत्व में की गई थी जिनके कुशल नेतृत्व और प्रयास के कारण इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर महिला से 30 लाख की ठगी

पलवल। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने पलवल की एक महिला से 30 लाख नौ हजार 510 रुपये ठग लिए। मामले की जांच कर रही पलवल साइबर अपराध थाना पुलिस ने ठगी की रकम में से 21.50 लाख रुपये एक निजी कंपनी के खाते में पहुंचने के बाद कंपनी के निदेशक को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित को न्यायालय में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साइबर अपराध थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी मनीषा कुमारी ने शिकायत दी थी कि कुछ लोगों ने वाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया। आरोपितों ने खुद को शेयर बाजार से जुड़ा बताया और उन्हें एक वाट्सएप समूह में जोड़ लिया। इसके बाद शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक फर्जी मोबाइल एप डाउनलोड कराया गया। आरोपितों के झांसे में आकर मनीषा ने 26 अगस्त से चार सितंबर के बीच अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कुल 30 लाख नौ हजार 510 रुपये बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए।

गाजियाबाद में 19 सितंबर तक रेल यातायात प्रभावित, 18 ट्रेनें रद और कई के बदले रूट

गाजियाबाद। गाजियाबाद यार्ड में पावर और ट्रैफिक ब्लाक के कारण रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन समय में फेरबदल किया गया है, जबकि कुछ गाड़ियों को पूरी तरह से निरस्त और उनके मार्ग बदले गए हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यार्ड ब्लाक के चलते रेलवे ने ट्रेन नंबर 54075 बरेली से दिल्ली जंक्शन की गाड़ी 14 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर 2026 को पूरी तरह रद कर दिया है। इससे जुड़ी लिंक ट्रेनें जैसे ट्रेन नंबर 54085 दिल्ली जंक्शन से सांतरोड, ट्रेन नंबर 54086 सांतरोड से दिल्ली जंक्शन और ट्रेन नंबर 54076 दिल्ली जंक्शन से बरेली की सेवाएं 15 सितंबर, 17 सितंबर और 19 सितंबर 2026 को नहीं चलेंगी। ट्रेन नंबर 15091 दौरई से टनकपुर की 14 सितंबर 2026 की यात्रा के लिए गाजियाबाद से मेरठ सिटी, टपरी, रुड़की और लक्सर जंक्शन होते हुए मुरादाबाद के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 13065 हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल की 17 सितंबर 2026 की गाड़ी मुरादाबाद से लक्सर जंक्शन, रुड़की, टपरी और मेरठ सिटी होते हुए गाजियाबाद के रास्ते डायवर्ट रहेगी। इस दौरान यह ट्रेन गजरौला जंक्शन और हापुड़ स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। ट्रेन नंबर 04013 लौकाहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल की 13, 15 और 17 सितंबर 2026 की ट्रेनें मुरादाबाद से लक्सर जंक्शन, रुड़की, टपरी और मेरठ सिटी होते हुए गाजियाबाद के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेंगी और इनका भी कोई स्टापेज नहीं काटा गया है। ब्लाक के दौरान समय प्रबंधन और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए कई गाड़ियों को उनके शुरुआती स्टेशनों पर देरी से चलाने या रास्ते में रोकने का निर्णय लिया गया है। टनकपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 15092 टनकपुर से दौरई की गाड़ी 14, 16 और 18 सितंबर 2026 को अपने निर्धारित समय से न चलकर 90 मिनट की देरी यानी रात 19:50 बजे टनकपुर से रवाना होगी। ट्रेन नंबर 15014 काठगोदाम से जैसलमेर की गाड़ी 14 व 16 सितंबर को 60 मिनट और 18 सितंबर को 75 मिनट रोकी जाएगी। ट्रेन नंबर 14205 अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की गाड़ी 14 व 16 सितंबर को 35 मिनट और 18 सितंबर को 50 मिनट रोकी जाएगी।

वैदिक विधि-विधान, मंत्रोच्चार और शुद्धीकरण के बाद अलाउद्दीन बने अखिलेश

लोनी। लोनी में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया है। मंगलवार को लोनी बार्डर स्थित हिंदू रक्षा दल के सनातन भवन में मुस्लिम धर्म के युवक ने वैदिक विधि-विधान, मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ शुद्धीकरण करने और जनेऊ धारण करने के बाद युवक का नया नाम अखिलेश रखा गया। अलाउद्दीन से अखिलेश बने युवक ने कहा कि मुझे बचपन से ही ही सनातन धर्म से प्यार रहा है। सनातन का गहराई से अध्ययन करने के बाद बिना किसी दबाव में उन्होंने यह निर्णय लिया है। मूलरूप से बिहार समस्तीपुर के रहने वाले अलाउद्दीन पिछले दो दशक से अधिक समय से ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की नसीब विहार कालोनी में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी, एक बेटी और चार बेटे है। वह राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। उन्होंने धर्म बदलने के बाद बताया कि सनातन धर्म का अध्ययन करते थे। किताबों को पढ़ने और अच्छी तरह समझकर ही अपनी मर्जी से सनातन में आने का निर्णय लिया। वह बचपन से सनातन धर्म को प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में मुझे जो सम्मान और स्नेह मिला है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। सनातन धर्म की अच्छाइयों का प्रचार-प्रसार करने के साथ साथ लोगों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। धर्म बदलने से पहले डर लगता था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमित प्रजापति ने बताया कि अलाउद्दीन ने खुद उनके पास आकर सनातन धर्म अपनाने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद सनातन भवन में पूर्ण विधि-विधान से हवन-पूजन कराने के बाद शुद्धिकरण कर जनेऊ धारण कराया गया। सनातन भवन में मौजूद लोगों ने अखिलेश के साथ हवन में आहुतियां दी। जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आना चाहता है, उसका हिंदू रक्षा दल स्वागत करता है।

सनातन में आने वाले हर व्यक्ति को संगठन की तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनके मान-सम्मान की रक्षा होगी और उनके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

गाजियाबाद में 26,384 वाहनों पर ईंधन का संकट

गाजियाबाद,एजेंसी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के चलने वाले वाहनों को एक अक्टूबर से ईंधन देने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' पॉलिसी जिले में ट्रायल के तौर पर अभी लागू की गई है, एप के माध्यम से वाहनों की पहचान की जा रही है। एक अक्टूबर से पालिसी को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

जिले में कुल 26,384 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या 20,193 है। कारों की संख्या 6,070 है। इनके अलावा 108 ट्रैक्टर, एक एंबुलेंस, एक गुडस कैरियर वाहन और नो बसों का भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नही है। जिले में वाहनों में ईंधन की आपूर्ति के लिए 135 पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंप हैं। नई व्यवस्था के तहत एक अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल व सीएनजी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। नियम के तहत ऐसे वाहनों की पहचान के लिए सितंबर माह तक सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे

(एएनपीआर) लगाए जाने हैं, लेकिन अब तक एक भी पेट्रोल पंप पर अब तक एएनपीआर कैमरे नहीं लगे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एएनपीआर कैमरे के विकल्प के रूप में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अभी पीयूसीसी के बिना चल रहे वाहनों की पहचान के लिए एप तैयार किया है। यह एप पेट्रोल पंप पर सभी सेल्समैन को मोबाइल में इंस्टाल करने के लिए कहा गया है। पेट्रोल पंप पर जब वाहन स्वामी ईंधन लेकर पहुंचेंगे तो सेल्समैन पहले वाहन का नंबर एप पर डालकर सर्च करेगा कि वाहन का पीयूसीसी है या नहीं। अभी इस व्यवस्था को ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। जिन वाहनों को पीयूसीसी नहीं है, उनको ईंधन लेने से पहले वाहन को पीयूसीसी बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने खुद भी पेट्रोल पंपों पर जाकर एप के माध्यम से वाहनों को चेक किया, इस दौरान कई वाहन का पीयूसीसी न मिलने पर वाहन स्वामी को चेताया गया है।

छात्र युवाओं के लिए राहुल वर्तमान और भविष्य, मोदी अतीत

शकील अख्तर

जनता समझ चुकी है कि उसे हिन्दू-मुसलमान के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाया गया। उसकी जिन्दगी खराब कर दी। और अगर अब भी वह चुप रही हिन्दू-मुसलमान के नशे में डूबी रही तो उसके बच्चों की जिन्दगी भी खराब हो जाएगी। खुद बच्चे भी यह समझ गए हैं। इसलिए पहले छात्र और युवा आए जिन्हें जेन जी कहा गया फिर स्कूली बच्चे, किशोर। जो जेन अल्फा कहला रहे हैं। 16 साल तक के लड़के-लड़कियां। क्स और इस तरह के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन थोड़े दिनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अन्दर के डर को कम कर देते हैं। यहां फोटो में सेंटर में रहने से वे समझते हैं कि देश की राजनीति में भी वे उसी तरह केन्द्र में हैं। मगर वह बात अतीत हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री केवल गोदी मीडिया और मेजबान की हैसियत से ऐसे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में ही सेंटर पाइंट में दिखते हैं। इससे पहले 2023 में यहीं दिल्ली में जी-20 के शिखर सम्मेलन में भी मोदी जी ऐसे ही खुद में आत्मविश्वास भर रहे थे। 400 पार की बात करने लगे थे।

लेकिन वे जो देश का विश्वास खो चुके थे वह 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में सामने आ गया। 400 पार का दावा 240 पर आकर रूक गया। जनता को भूलकर केवल गोदी मीडिया में जीने का नतीजा सामने आ गया। अब फिर मोदी जी सब भूलकर इस ब्रिक्स सम्मेलन को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह लेंगे। गोदी मीडिया उन्हें चढ़ा ही रहा है। लेकिन इससे वापस उनके देश के सेंटर पांइट में आने की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। जगह भर चुकी है। वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आ चुके हैं। चार साल पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके गेम पलट दिया था। लेकिन देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा होने के कारण मोदी 2024 में पूरी तरह पराजित नहीं हो सके। राहुल ने इस चुनाव के बाद दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं। एक अगर चुनाव ईमानदारी से होते तो मोदी को सौ सीटों का और नुकसान होता। और दूसरे अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जातीं तो मोदी हार जाते। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने ही मोदी को 7 राउंड तक पीछे छोड़ रखा था। लेकिन उसके बाद खेल बदला गया। फिर भी मोदी 2019 के मुकाबले काफी कम अंतर से जीत दर्ज कर पाए। 2019 में 4 लाख 79 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे और 2024 में केवल 1 लाख 52 हजार वोटों से। 2014 के चुनाव में भी 3 लाख 71 हजार वोटों का अंतर था। मगर 2024 वाटर लू होते होते बचा। उसके बाद से मोदी वापस अपना आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। कहां वे भारत की कुशल वायुसेना को यह तक बता देते थे कि पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने के लिए जहाज को तब लेकर जाओ जब बादल हों।

इतने अति आत्मविश्वास में होते थे कि साइंस की नई खोज कर दी थी कि बादलों में रडार काम नहीं करता है। सेना को चुप रह जाना था। वह रही और अपना काम कर आई। मगर मोदी उस समय ऐसे ही आत्मविश्वास में थे कि जो मैं कहूंगा वह हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नाले के गैस से चाय बन सकती है। तो यह सब जीत का आत्मविश्वास था। लग रहा था कि मैं हार ही नहीं सकता। जनता वही करेगी जो मैं चाहूंगा। जनता के लिए मैं कुछ करूं, ना करूं! जनता को मुझ में कुछ दिखता है। जिसे उन्होंने बाद में ईश्वरीय अंश भी कहा था। खुद को नान बायलोजिकल। सीधे अवतरण। तो एक वह दौर था। लेकिन उसे फिर राहुल ने अपनी दो यात्रा, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर वहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने रोज नई चुनौती पेश करके ऐसा बदला कि अभी पिछले लोकसभा के मानसून सत्र में मोदी और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी अमित शाह दोनों लोकसभा में आ ही नहीं पाए। खेल इस तरह बदल जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। संसद के इससे पहले के बजट सत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने लोकसभा में नहीं आ पाए। साफ तौर पर कारण डर को बताया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने उन्हें मना किया। सदन में उन्हें विपक्ष की महिला सदस्यों की तरफ से खतरा था! ऐसा कभी नहीं हुआ। एक कि प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब न दें। और दूसरे वे सदन के अंदर महिला सदस्यों से खतरा महसूस करें। यहीं से बाजी पलटना शुरू हो गई। इसलिए अब केवल ऐसे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों से ही मोदी कुछ समय के लिए आत्मविश्वास पाते हैं। मगर फिर जल्दी ही सच्चाई का सामना हो जाता है कि छात्र और युवा भारी आक्रोश में हैं। जनता की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनके पास इन सबका कोई हल नहीं है। उनका एकमात्र दांव हिन्दू-मुसलमान चल नहीं पा रहा है। जनता समझ चुकी है कि उसे हिन्दू-मुसलमान के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाया गया। उसकी जिन्दगी खराब कर दी। और अगर अब भी वह चुप रही हिन्दू-मुसलमान के नशे में डूबी रही तो उसके बच्चों की जिन्दगी भी खराब हो जाएगी। खुद बच्चे भी यह समझ गए हैं। इसलिए पहले छात्र और युवा आए जिन्हें जेन जी कहा गया फिर स्कूली बच्चे, किशोर। जो जेन अल्फा कहला रहे हैं। 16 साल तक के लड़के-लड़कियां।

राहुल इन सबकी आवाज बने। 17 जून को उन्होंने कोटा में छात्रों का एक पहला सम्मेलन किया। उसकी सफलता के बाद देहरादून, प्रयागराज, पुणे जो केवल छात्रा सम्मेलन था और अभूतपूर्व सफल हुआ के बाद अब वे इन्दौर में इस गूंज सीरिज का पांचवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पिछले चारों मौकों पर राज्य सरकारों ने सम्मेलन की जगह देने में आखिरी आखिरी तक व्यवधान डाले। जगह दे कर कैंसिल की। देहरादून में जो जगह पहले दी थी उसे कैंसिल की और वहीं म्यूजिक का बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिया कि आज की युवा पीढ़ी इसमें बहुत रुचि लेती है वहां आ जाएगी। प्रोग्राम भी बिना टिकट का। मगर छात्र वहां न जाकर राहुल के प्रोग्राम में पहुंचे। प्रयागराज में तो सभा स्थल पर सीवर का गंदा पानी छोड़ दिया गया। लेकिन यह सारी बाधाएं न राहुल को रोक पाईं, न छात्रों को। अब इन्दौर में छात्रों के सम्मेलन के लिए जो जगह मांगी थी नेहरू स्टेडियम नहीं दी। कांग्रेस का ही बनाया हुआ है और कांग्रेस छात्रों के लिए मांग रही है मगर नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 23 साल से भाजपा की सरकार है। कुछ इन्होंने बनाया? नहीं। मगर जो कांग्रेस का बनाया हुआ है वह भी नहीं दे रहे। दूसरी जगह रीजनल पार्क के सामने का मैदान मांगा। काफी अड़ंगे डालने के बाद उसके लिए दस लाख से ज्यादा रुपए जमा करवाए। वह भी कांग्रेस ने कर दिए। मगर फिर भी अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं मिली है। यह किसका डर है? छात्रों का? राहुल का? या दोनों का? यह डर अब शिफ्ट हो गया है। पहले जनता डरी हुई थी। अब सरकार डरी हुई है। छात्र और युवाओं के सामने आने से सब में हौसला आया है। प्रधानमंत्री मोदी जो अतीत की यहां तक कि हजार साल पहले तक की बात करके लोगों को बहकाते थे वे अब सफल नहीं हो रहे हैं। राहुल की वर्तमान की, भविष्य की बातें लोगों को खास तौर से छात्रों, युवाओं का समझ में आने लगी हैं। नफरत और विभाजन के परिणाम उन्होंने देख लिए। पहले हिन्दू-मुसलमान किया। अब जाति-जाति को आपस में लड़वा दिया। देश में इस समय अगड़े-पिछड़े के बीच जो तनाव आरोप प्रत्यारोप और यहां तक कि सोशल मीडिया पर गाली-गलौज तक चल रहा है वह भयावह है। नई पीढ़ी इसे समझ गई है कि मोदी केवल नफरत और विभाजन की राजनीति ही जानते हैं। और अब उसके भी खत्म होने का समय आ गया है। छात्र युवाओं का समय भी यहीं से शुरू हो रहा है। अपना भविष्य बनाने का। और उसमें उन्हें अब मोदी की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। राहुल में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है।

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का आयात 21.43 अरब डॉलर और निर्यात महज 6.03 अरब डॉलर रहा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए वर्ष 2011 में लागू हुए 15 साल पुराने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीपा) की समीक्षा करने और इसके दायरे को बढ़ाने की बात कही गई है। भारत मुख्य रूप से अपने बासमती चावल, कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए जापानी बाजार में बेहतर पहुंच की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है। वर्ष 2026 की पहली छमाही जनवरी से जून में चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से यह घाटा और चुनौतीपूर्ण हुआ है। वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार घाटा 67.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। दोनों देशों के बीच कुल कारोबार 91.72 अरब डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने चीन से 79.41 अरब डॉलर का सामान मंगवाया। भारत की ओर से चीन को मात्र 12.31 अरब डॉलर का सामान बेचा गया। चीन से भारत में लगातार बढ़ता आयात और उसकी तुलना में अत्यंत कम निर्यात ही इस विशाल व्यापार घाटे की मुख्य वजह है।

बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के तहत भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार असंतुलन की चिंता को भी प्रस्तुत किया। कहा गया कि वर्ष 2025-26 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 416 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत का कुल आयात 320 अरब डॉलर का है, यह आयात मुख्य रूप से ऊर्जा (कच्चा तेल, गैस) और विनिर्माण इनपुट (इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी) पर केंद्रित है। ब्रिक्स देशों को भारत का कुल निर्यात लगभग 96 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। यद्यपि ब्रिक्स देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा बढ़ी है, लेकिन भारत के लिए 224 अरब डॉलर का भारी-भरकम व्यापार घाटा एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत के विदेश व्यापार पर प्रकाशित हालिया राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत के व्यापार घाटा बढने पर महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सितंबर 2026 की रिपोर्ट में भारत के बढ़ते व्यापार घाटे और उसके प्रभावों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर के पहले सप्ताह में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़कर 4.2 अरब डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वस्तु व्यापार घाटे में 25 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। वैश्विक संगठन मैकिन्से ग्लोबल ट्रेड अपडेट सितंबर 2026 के अनुसार मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल तथा कोयले की वैश्विक कीमतों में वृद्धि ने भारत के आयात बिल और व्यापार घाटे को रिकार्ड स्तर पर पहुंचा दिया है।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक घटकों की बढ़ती मांग ने चीन से होने वाले आयात को और बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के तहत अप्रैल-अगस्त के दौरान भारत का वस्तु निर्यात करीब 15 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन आयात में 19 प्रतिशत से अधिक की तीव्र वृद्धि के कारण विदेश व्यापार घाटा ऊंचाई पर पहुंच गया है। कच्चे तेल और ईंधन की ऊंची वैश्विक कीमतें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, उर्वरक और सोने के अधिक आयात के कारण विदेश व्यापार घाटा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का कई प्रमुख देशों के साथ व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता व्यक्त की। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का आयात 21.43 अरब डॉलर और निर्यात महज 6.03 अरब डॉलर रहा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए वर्ष 2011 में लागू हुए 15 साल पुराने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीपा) की समीक्षा करने और इसके दायरे को बढ़ाने की बात कही गई है। भारत मुख्य रूप से अपने बासमती चावल, कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए जापानी बाजार में बेहतर पहुंच की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है। वर्ष 2026 की पहली छमाही जनवरी से जून में चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से यह घाटा और चुनौतीपूर्ण हुआ है। वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार घाटा 67.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। दोनों देशों के बीच कुल कारोबार 91.72 अरब डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने चीन से 79.41 अरब डॉलर का सामान मंगवाया। भारत की ओर से चीन को मात्र 12.31 अरब डॉलर का सामान बेचा गया। चीन से भारत में लगातार बढ़ता आयात और उसकी तुलना में अत्यंत कम निर्यात ही इस विशाल व्यापार घाटे की मुख्य वजह है। भारत मुख्य रूप से चीन से बिजली के उपकरण, दूरभाष के पुर्जे, कंप्यूटर उपकरण, अर्द्धचालक (सेमीकंडक्टर), बैटरी और औद्योगिक मशीनरी का आयात करता है। यदि हम भारत-रूस व्यापार की ओर देखें तो पाते हैं कि चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक रूस से भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रूस से भारत का आयात 52.59 प्रतिशत बढ़कर 23.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

आयात में इस वृद्धि का मुख्य कारण कच्चा तेल है, जिसकी खरीद में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल के अलावा भारत रूस से उर्वरक, पशु/वनस्पति चर्बी और अर्ध-कीमती पत्थर भी आयात करता है। ऐसे में व्यापार का संतुलन पूरी तरह से रूस के पक्ष में झुका हुआ है। पश्चिमी प्रतिबंधों और अमरीका के राजनीतिक दबाव के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत का व्यापार घाटा प्रमुख रूप से मध्य पूर्व और एशियाई देशों संयुक्त अरब अमीरात, इराक और सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग जैसे देशों के साथ भी बना हुआ है। अमरीका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने के बाद भी भारत से अमरीका को निर्यात अमरीका से भारत में आने वाले आयात की तुलना में अधिक है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में भारत का व्यापार घाटा 31.98 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो कि पिछले छह महीनों का उच्चतम स्तर है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई के चार महीनों में व्यापार घाटा बढ़कर 118 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के चार महीनों का प्रदर्शन भी देश के बढ़ते व्यापार असंतुलन की तस्वीर साफ करता है। अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल आयात सालाना आधार पर 19.3 प्रतिशत बढ़कर 292.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसी चार महीने की अवधि में वस्तु निर्यात 17 प्रतिशत बढ़कर 173.78 अरब डॉलर दर्ज किया गया। व्यापार घाटे के इस स्तर पर पहुंचने के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात में हुई बढ़ोतरी जिम्मेदार है।

नि:संदेह, देश के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए रणनीतिपूर्वक आगे बढना होगा। हरित ऊर्जा और इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देना होगा। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जाना होगा। सौर और पवन ऊर्जा के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर औद्योगिक ऊर्जा मांग को ग्रिड-आधारित हरित ऊर्जा पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे तेल व कोयला आयात बिल में अरबों डॉलर की बचत होगी। ई-वाहनों का तेजी से अपनाव जरूरी है। सार्वजनिक और निजी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू खपत घटेगी, जिसका सीधा असर आयात बिल में कमी के रूप में दिखेगा। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के आंकड़े केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि रणनीति बदलने का अवसर हैं। व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाने की बजाय आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विविधीकरण और सेवा क्षेत्र के विस्तार की रणनीति के साथ आगे बढना होगा। यदि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में हरित बदलाव लाता है, ढुलाई लागत घटाता है, उच्च स्तरीय विनिर्माण को गति देता है और सेवा क्षेत्र को नए वैश्विक मॉडलों पर ले जाता है, तो निश्चित रूप से व्यापार घाटा नियंत्रण में रह सकेगा।

विचार

पर्युषण आत्मशांति की वह साधना जो जीवन की दिशा बदल देती है

कांतिलाल मांडोत

वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य सुख-सुविधाओं से घिरा होने के बावजूद भीतर से अशांत है। संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है, लेकिन शांति की तलाश में मनुष्य लगातार बाहर की ओर भटक रहा है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सुविधा और भौतिक उपलब्धियों को शांति का साधन मान लेने के कारण उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। स्थिति उस कस्तूरी मृग जैसी हो गई है जो सुगंध का स्रोत अपने भीतर होने के बावजूद उसे जंगल-जंगल खोजता रहता है। पर्युषण महापर्व इसी बाहरी भटकाव से भीतर की यात्रा की ओर लौटने का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में सुख और शांति एक नहीं हैं। सुख किसी वस्तु की प्राप्ति से मिल सकता है, लेकिन शांति वस्तुओं की अधिकता से नहीं आती। मनुष्य की कामनाएं जब किसी वस्तु की प्राप्ति के बाद कुछ समय के लिए शांत होती हैं तो उसे सुख का अनुभव होता है, लेकिन थोड़े ही समय में मन फिर कहता है कि अभी और चाहिए। यही चाह मनुष्य को निरंतर दौड़ाती रहती है। इसके विपरीत जिज्ञासा मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। वह पूछती है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और स्थायी संतोष कहां से प्राप्त होगा। पर्युषण इसी जिज्ञासा को जागृत करने वाला पर्व है।

पर्युषण का महत्व इसलिए भी असाधारण है कि यह मनुष्य को संग्रह से त्याग और भोग से संयम की ओर ले जाता है। संसार में सुख का रास्ता अधिक पाने से जुड़ा दिखाई देता है, जबकि आत्मशांति का मार्ग छोड़ने, बांटने और अपरिग्रह से होकर गुजरता है। जितना अधिक मनुष्य पदार्थों को पकड़ता है, उतना ही उसके भीतर भय, मोह और असुरक्षा बढ़ती है। इसके विपरीत त्याग मन को हल्का करता है। पर्युषण के दिनों में तप, उपवास, एकासन, आयंबिल, पौषध, स्वाध्याय, सामायिक और प्रतिक्रमण जैसी साधनाएं इसी आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। मनुष्य के अशांत होने का एक बड़ा कारण उसकी धारणाएं भी हैं। कई बार वास्तविक समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। जैसे रेल के डिब्बे में खिड़की खोलने और बंद करने को लेकर दो यात्रियों के बीच विवाद हुआ, जबकि खिड़की में कांच ही नहीं था। दोनों अपनी-अपनी धारणा को सत्य मानकर लड़ते रहे। वास्तविकता का पता चलते ही विवाद समाप्त हो गया। हमारे जीवन में भी अनेक अशांतियां ऐसी ही धारणाओं से पैदा होती हैं। पूर्वाग्रह, अहंकार, आग्रह और मोह की खिड़कियां बंद रहते हुए हम सत्य को पूरी तरह देख नहीं पाते। पर्युषण इन खिड़कियों को खोलने का अवसर है। पर्युषण केवल धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण की जीवंत साधना है। इस पर्व में व्यक्ति कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से स्वयं को अलग कर अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करता है। तप शरीर को अनुशासित करता है, जप मन को एकाग्र करता है, स्वाध्याय विचारों को दिशा देता है और प्रतिक्रमण व्यक्ति को अपने कर्मों तथा भूलों का बोध कराता है। इस प्रक्रिया में आत्मा और व्यवहार के बीच बनी दूरियां कम होने लगती हैं। यही इस पर्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर्युषण का एक महत्वपूर्ण संदेश अपरिग्रह भी है। आज की जीवनशैली में आवश्यकता और लालसा के बीच का अंतर लगातार मिटता जा रहा है। मनुष्य जरूरत से अधिक पाने को ही सफलता समझने लगा है। लेकिन अधिक संग्रह हमेशा अधिक संतोष नहीं देता। कई बार संग्रह ही चिंता का कारण बन जाता है। पर्युषण व्यक्ति को यह समझाता है कि जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल बाहर जमा की गई वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर विकसित किए गए संयम, करुणा, क्षमा, संतोष और आत्मविश्वास में है। इस पर्व का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष क्षमायाचना और आत्मशुद्धि है। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भूल स्वीकार करना और उसे सुधारने का साहस ही उसके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है। पर्युषण व्यक्ति को दूसरों की गलतियां गिनने से पहले स्वयं के आचरण को देखने की प्रेरणा देता है। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा मांगना केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं बल्कि मन के बोझ को उतारने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्षमा संबंधों को ही नहीं, स्वयं के अंतर्मन को भी हल्का करती है। आज जब जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा, उपभोग और असंतोष बढ़ रहा है, तब पर्युषण की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। यह पर्व हमें कुछ दिनों के लिए जीवन की गति धीमी करके यह देखने का अवसर देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में कहीं हमने अपने भीतर की शांति तो नहीं खो दी। पर्युषण इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की साधना है। आठ दिनों की पर्युषण साधना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि यह केवल आठ दिन चलती है, बल्कि इसलिए कि यह आठ दिनों में जीवन जीने की नई दृष्टि दे सकती है।

एक नजर

स्टेशन रोड के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 महिला, एक युवक और मैनेजर गिरफ्तार

डेहरी-आन-सोन। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल अनीश में प्रशासन ने मंगलवार देर शाम छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। होटल के कमरे से चार महिलाएं, एक पुरुष और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम निलेश कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड के होटलों में देह व्यापार की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। इसी के आलोक में मंगलवार शाम होटल अनीश में छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में चार महिला और एक पुरुष मिले, साथ ही होटल मैनेजर ओम प्रकाश को भी हिरासत में लिया गया। तलाशी में कमरे से भारी मात्रा में कंडोम और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। होटल के रजिस्टर में किसी का नाम दर्ज नहीं था। होटल संचालन में मानकों की अनदेखी की जा रही थी। सभी गिरफ्तार बालिग हैं। एसडीएम ने बताया कि महिलाओं से पूछताछ की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में प्रभारी एसडीपीओ संजीव कुमार, नगर थानाध्यक्ष राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे।

नेपाल में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए बिहार में उनके परिजनों के डीएनए सैंपल संग्रह एवं जाँच की होगी व्यवस्था

पटना। नेपाल में हाल में हुई भीषण त्रासदी के दौरान लापता हुए व्यक्तियों की पहचान में सहयोग के उद्देश्य से बिहार सरकार के गृह विभाग ने उनके परिजनों के डीएनए सैंपल संग्रह एवं जाँच की आवश्यक व्यवस्था की है। नेपाल त्रासदी में लापता व्यक्तियों के ऐसे परिजन, जो बिहार में निवास करते हैं और अपने लापता परिजन की पहचान की प्रक्रिया में डीएनए सैंपल उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के माध्यम से आवश्यक सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गृह विभाग, बिहार सरकार ने मीडिया के माध्यम से मंगलवार को संबंधित पीड़ित परिवारों से अपील की है कि वे अपने स्थानीय पुलिस, प्रशासन से संपर्क कर डीएनए सैंपल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त करें। विभाग की ओर से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पीड़ित परिवारों को डीएनए सैंपल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हरसंभव सहायता प्रदान करें। डीएनए की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के द्वारा की जाएगी। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या 0612-2294073 पर संपर्क किया जा सकता है।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर निकायों को दिए गए सख्त निर्देश

बक्सर। आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नगर निकायों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी नगर निकायों को वार्ड स्तर तक पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के दौरान महत्वपूर्ण घाटों, मंदिरों एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर विशेष साफ-सफाई के साथ दीप प्रज्वलन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पहले से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या को लेकर नालों की नियमित उड़ाही और साफ-सफाई कराने तथा डोर-टू-डोर कचरा उठाव को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा चौक-चौराहों पर लाइटिंग और पेंटिंग कराने को कहा गया। सदर अस्पताल परिसर को भी अभियान के तहत बेहतर स्वरूप देने के लिए सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर पेंटिंग कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए 'सेवा संकल्प अभियान' को सफल बनाने की हिदायत दी।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाई गंभीर घायल

सुपौल। त्रिवेणीगंज-जदिया मार्ग पर मंगलवार को पांडेडपट्टी हरिनाहा चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों सड़क किनारे गिर पड़े। सूचना मिलने पर जदिया थाना की गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। जदिया गश्ती दल के एएसआई तारानंद भारती ने बताया कि पांडेडपट्टी हरिनाहा चौक के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में दोनों युवक घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अनुमंडलीय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक उमेश कुमार मंडल ने बताया कि दोनों घायलों की स्थिति गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी शिव ऋषि देव के पुत्र योगेंद्र ऋषि देव और नरेश ऋषि देव के रूप में हुई है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।

बिहार कैबिनेट के 17 प्रस्तावों पर मुहर, गयाजी कॉरिडोर के लिए 2520 करोड़ मंजूर

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, खनन, पर्यटन, विमानन, बाढ़ सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने गयाजी के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए 2520 करोड़ रुपये तथा सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना के लिए 996 करोड़ पांच लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधीन पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 366 पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी है। इन चिकित्सा महाविद्यालयों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया, पूर्णिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा-सारण और राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 89 करोड़ 79 लाख 68 हजार 400 रुपये की स्वीकृति दी गई। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पैरावेट स्कूल की स्थापना के लिए चार अनुदेशक और दो निम्नवर्गीय लिपिक समेत छह पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 45 लाख 98 हजार 832 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। बैठक में बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई। साथ ही बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली-2026

की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) केंद्र प्रायोजित योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वयन के लिए दो करोड़ 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी। योजना का उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक 78 करोड़ 34 लाख 22 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने ईंट-भट्ठा मालिकों को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बकाया रखने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों को ब्याज की राशि छोड़कर मूल बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा। मूल राशि जमा करने के बाद संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी यह रिपोर्ट करेंगे कि देनदार पर कोई लोक मांग बकाया नहीं है। इसके आधार पर नीलाम पत्रवाद का निस्तारण किया जाएगा। योजना की अवधि तीन माह होगी। राज्य सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से एक हजार करोड़ रुपये की निकासी को भी मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति यात्रा से संबंधित कार्यों, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों, जल-जीवन-हरियाली अभियान और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर किया जाएगा। बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। ये पद अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

गयाजी के विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके लिए 2520 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना के निर्माण के लिए 996 करोड़ पांच लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। दोनों योजनाओं के लिए कुल 3516 करोड़ पांच लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य की जेलों के आसपास उपलब्ध खाली जमीन का उपयोग करते हुए पेट्रोल पंप खोलने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट परिचालन नियमावली-2026 के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पूर्णिया और मुजफ्फरपुर की जेलों में इंडियन ऑयल तथा बक्सर और भागलपुर की जेलों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप संचालित किए जाएंगे। कंपनियों का चयन नामांकन के आधार पर किया गया है। इसके अलावा राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत विभिन्न हवाई अड्डों के विकास और जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई।

सुपौल में पत्रकारों की बैठक सहरसा सदर अस्पताल में पत्रकार से मारपीट के विरोध में पत्रकार एकजुट

सुपौल। सहरसा जिले में खबर संकलन के दौरान सदर अस्पताल में पत्रकार के साथ चिकित्सक द्वारा मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना के विरोध में मंगलवार को जिला मुख्यालय में विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एकजुटता प्रदर्शित की। बैठक के दौरान सहरसा की घटना को लेकर उपस्थित पत्रकारों से विचार आमंत्रित किए गए। पत्रकारों ने अपने-अपने विचार रखते हुए घटना पर चिंता जताई और कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस पहल जरूरी है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किसी भी पत्रकार के साथ होने वाली घटना को व्यक्तिगत मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पत्रकार बिरादरी को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि यदि मंगलवार की रात तक संबंधित मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकारों की ओर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उपस्थित पत्रकारों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। हालांकि, आंदोलन के स्वरूप और आगे की रणनीति पर पत्रकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्णय लेने की बात कही गई। पत्रकारों ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और पत्रकारों का काम जनता की समस्याओं तथा घटनाओं को सामने लाना है। खबर संकलन के दौरान पत्रकारों को धमकाने, रोकने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी तरीके से रोक लगनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को भी पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। बैठक में यह भी कहा गया कि पत्रकारों को अपना काम निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलना आवश्यक है। किसी भी पत्रकार के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार की घटना न केवल संबंधित पत्रकार को प्रभावित करती है, बल्कि इससे पूरे मीडिया जगत में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा की गई। बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने सहरसा की घटना के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार हित और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जिले के सभी पत्रकारों को आपसी मतभेद से ऊपर उठकर एक मंच पर आने की जरूरत है।

शिक्षा वही जो समाज के काम आए और कल्याण करेः ख्यालीराम

भागलपुर। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरगाकोठी, चंपानगर भागलपुर में मंगलवार को क्षेत्रीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र का प्रारंभ मुख्य अतिथि विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्यालीराम, उत्तर बिहार के प्रदेश सचिव रामलाल सिंह, महाविद्यालय के अध्यक्ष पवन पोद्दार, सदस्य शरद चंद्र राय एवं प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्यालीराम ने कहा कि शिक्षा वही है जो समाज के काम आए और जिससे समाज का कल्याण हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर वर्ष लगने वाले इस अभ्यास वर्ग में कुछ नया सीखने की इच्छा शक्ति को प्रबल रखना होगा। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ही संगठन को मजबूत बनाती है। ज्ञान और बुद्धि की पराकाष्ठा आनंद की प्राप्ति तक होनी चाहिए। उन्होंने डॉ. आंबेडकर के कथन को दोहराते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा। हमें अपनी शिक्षा को स्वयं तक सीमित न रखकर समाज हित में लगाना है और संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना है। उत्तर बिहार के प्रदेश सचिव रामलाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्या भारती पूरे विश्व में सबसे बड़ा गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान है। इसका विशाल कार्य पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से ही सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज संगठन के सभी पूर्णकालिकों को शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा।

संस्कृति ज्ञान परियोजना के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को मिलकर पूरा करना है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा महाविद्यालय से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित 'दृष्टि' पत्रिका का विमोचन किया गया। इससे पूर्व, अतिथियों का परिचय झारखंड के प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा द्वारा कराया गया। उद्घाटन सत्र के समापन के बाद पर्यावरण संतुलन और प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए महाविद्यालय परिसर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा सुपाड़ी, रुद्राक्ष, अशोक, तेजपत्ता, महोगनी और पारिजात के पौधों का रोपण किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग और सीएएफ के बीच समझौता, सीईपीट के तकनीकी सहयोग से विकसित होगी टाउनशिप : नीतीश मिश्रा

पटना,एजेंसी। बिहार में सुनियोजित, आधुनिक एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शहरी विकास को नई दिशा देने की पहल के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग, मंत्री नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सेंटर फॉर इनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी फाउंडेशन (सीएएफ), अहमदाबाद के बीच तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू.) की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण समझौता किया गया। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार भी उपस्थित थे। समझौते पर नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार नगर विकास प्राधिकरण, नवल किशोर चौधरी तथा सी. ई. पी. टी. एडवाइजरी फाउंडेशन के निदेशक दर्शन पारिख ने हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

मंत्रीनीतीश मिश्रा ने कहा कि इस तकनीकी सहयोग के माध्यम से बिहार में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित एवं सतत विकास को गति मिलेगी। सीएएफ द्वारा आधुनिक शहरी नियोजन, स्थानिक विकास पहल, नीति निर्माण, भूमि उपयोग नियोजन, आधारभूत संरचना विकास तथा दीर्घकालिक शहरी विकास की रणनीति तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकसित एवं समृद्ध बिहार के विज़न के अनुरूप राज्य में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए एवं आधुनिक शहरी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा

कि सीईपीटी एडवाइजरी फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था के साथ यह सहयोग बिहार में सुनियोजित, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मंत्री मिश्रा ने कहा कि तकनीकी सहायता इकाई विभाग को डेटा आधारित, वैज्ञानिक एवं आधुनिक शहरी नियोजन के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। इसके माध्यम से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक-केंद्रित सुविधाओं से युक्त विकसित शहरी क्षेत्र के रूप में आकार देने में सहायता मिलेगी।

छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र

पटना। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से उनके 7, सर्कुलर रोड आवास पर हुई प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय से संबंधित अपनी आठ मुख्य मांगों का मांग पत्र सौंपा।

नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी दी कि वो लोग पिछले 8 दिनों यानि 7 सितंबर, 2026 से ही अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि छात्र-छात्राएं परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी और उन लोगों के खिलाफ नीतियों से परेशान हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही की वजह से उन सभी का भविष्य खतरे में है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से नीतीश कुमार के समक्ष अपनी आठ सुत्री मांगें रखी, जिनमें पढ़ाई सत्र का नियमितीकरण, टाइम टेबल को सुचारू करना और फीस माफी, स्थायी कुलपति की नियुक्ति और पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों की पदस्थापना, बैकलॉग और सप्लीमेंट्री परीक्षा की भारी फीस पर रोक, सिलेबस की स्पष्टता और पास होने के बराबर वस्तुनिष्ठ सवाल, कॉपी जांच में री-चेकिंग की सुविधा, मदद के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना और ससमय मार्कशीट की उपलब्धता, यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी की जांच और बिहार मेडिकल और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कानून 2026 पर दोबारा विचार शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार से उनकी मांगों को लेकर आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना एवं उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह की बात कही। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे।

सेवा, सुशासन और विकास के 25 वर्षों की यात्रा को जनभागीदारी से बनाएंगे ऐतिहासिक : नंद किशोर राम

पटना। बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की और पिछले 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा, विकास और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। उन्होंने देश के गरीब, वंचित, किसान, महिला, युवा और आम नागरिक की चिंता करते हुए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सहित अनेक योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिला है। कोरोना काल में देश के प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण का व्यापक अभियान चलाकर सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार और प्रधानमंत्री देशवासियों के स्वास्थ्य, कल्याण, विकास और भारत को विश्वगुरु बनाने की चिंता करते हैं, तो देशवासियों का भी दायित्व बनता है कि वे उन्हें अपना आशीर्वाद दें। इसी उद्देश्य से 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच देश और बिहार के गांव-गांव, घर-घर तथा समाज के सम्मानित लोगों से 'आशीर्वाद का दीप' जलाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बिहारवासियों सहित देशवासियों से अपील की कि वे इस अवसर पर दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

मंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया' की भावना के साथ युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 19 सितंबर को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज-सेवा संकल्प अभियान के पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगर विकास, कृषि और उद्योग विभागों को जोड़कर युवाओं के नवाचार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक माह चलेगा। प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अमृता भूषण राठौर ने कहा कि नेशनल इनोवेशन चैलेंज सेवा संकल्प अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्यक्रम बिहार के किसानों, युवाओं, छात्रों और विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने अभिनव विचारों के साथ समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं।

एक नजर

पैट कमिंस ने बताया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट हार का कारण, खराब तैयारी की बात को किया खारिज

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में मिली चौंकाने वाली टेस्ट हार के लिए खराब तैयारी को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया को दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए पारी और बड़ी जीत दर्ज की थी। कमिंस ने कहा कि अगर यह सीरीज बांग्लादेश के बजाय इंग्लैंड के खिलाफ एशेज जैसी बड़ी सीरीज होती, तब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तैयारी में कोई बदलाव नहीं होता। उन्होंने 'कीपिन' इट क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा, 'चाहे वह एशेज टेस्ट होता या बांग्लादेश सीरीज, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसी तरह तैयारी करते। निश्चित तौर पर आप सीरीज के बाद उसका आकलन करते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में लगा कि हम अच्छी स्थिति में थे। हर कोई फिट था और पूरी तरह तैयार था। पहले टेस्ट में क्या गलत हुआ, इस सवाल पर कमिंस ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह तैयारी की कमी थी। मुझे लगता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए और बांग्लादेश ने शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने हमें वास्तव में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया का अगला टेस्ट अभियान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से शुरू होगा। हालांकि, कमिंस इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज में नहीं खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका का यह दौरा 2018 के 'सैंडपेपरगेट' विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट में वहां वापसी भी होगा। हालांकि, कमिंस को उम्मीद नहीं है कि पुराना विवाद आगामी टेस्ट सीरीज पर हावी रहेगा। उन्होंने कहा, 'थोड़ी शत्रुता हो सकती है।' हालांकि, उन्होंने तुरंत कहा, 'हर कोई आगे बढ़ चुका है। अच्छी बात यह है कि तीन टेस्ट मैच हैं, आप क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बहुत जल्दी हर कोई सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचने लगता है। कमिंस ने कहा, 'मुझे यकीन है कि दर्शकों में कुछ लोग काफी शोर मचाएंगे और कुछ लेख या मीडिया फिर से पुरानी बातों को सामने ला सकते हैं। लेकिन हमारी टीम उस घटना से आगे बढ़ चुकी है।'

आईओसी और ओसीए अध्यक्ष 20 सितंबर को एशियाई खेलों के एथलीट गांव का दौरा करेंगे

नागोया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री और एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमाद अल थानी 19 सितंबर को उद्घाटन समारोह के एक दिन बाद 20 सितंबर को आइची-नागोया एशियाई खेलों के एथलीट गांव का दौरा करेंगे। सोमवार को यहां हुई दल प्रमुखों की बैठक में बताया गया कि कोवेंट्री और थानी गांव के गार्डन पियर क्षेत्र का दौरा करेंगे और विभिन्न राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। दोनों अध्यक्ष 20 सितंबर को सुबह 11 बजे गार्डन पियर जाएंगे। इससे एक दिन पहले 19 सितंबर को एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह होगा। आइची-नागोया एशियाई खेलों में पारंपरिक एथलीट गांव नहीं बनाया गया है। 45 एनओसी के खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था एक क्रूज जहाज, गार्डन पियर में बनाए गए एशियाई खेलों के अस्थाई विला और नागोया शहर तथा आइची प्रांत के विभिन्न होटलों में की गई है। क्रूज जहाज मंगलवार को नागोया बंदरगाह के किंजो पियर पर पहुंचेगा जहां दोपहर एक बजे स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ी अगले दिन से जहाज पर सवार होना शुरू करेंगे।

दल प्रमुखों की बैठक में टीम स्वागत समारोहों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। ये समारोह 16 से 18 सितंबर तक गार्डन पियर स्थित एथलीट्स प्लाजा के 'एथलीट्स इंटरैक्शन एरिया' में आयोजित किए जाएंगे। हर दिन तीन समारोह सुबह 10 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम पांच बजे होंगे। प्रत्येक समारोह 30 मिनट का होगा। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनओसी के ध्वज का आरोहण, राष्ट्रगान और स्मृति-चिह्नों का आदान-प्रदान शामिल होगा। प्रत्येक दिन पहले सत्र के दौरान वृक्षारोपण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। दो ताइक्वांडो खिलाड़ियों वाली ओसीए शरणार्थी टीम/एशियाई शरणार्थी टीम का 18 सितंबर को सुबह 10 बजे एथलीट गांव में आधिकारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। बैठक में प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों को यह भी बताया गया कि सुरक्षा एवं संरक्षण अधिकारियों की बैठक 21 सितंबर को होगी। वहीं, एनओसी टीम के डॉक्टरों की बैठकें 18 सितंबर और तीन अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। ई-स्पोर्ट्स ड्रॉ 17 सितंबर को होगा। वहीं एशियाई खेलों के दौरान होने वाले ओसीए एथलीट समिति के चुनाव से जुड़ी जानकारी 16 सितंबर को होने वाली अगली दल प्रमुख बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों का उद्घाटन 19 सितंबर को होगा और इनका समापन चार अक्टूबर को किया जाएगा।

शतरंज ओलंपियाड से पहले उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव को सौंपी गई मशाल

बेंगलुरु। शतरंज ओलंपियाड 2026 के लिए आधिकारिक उलटी गिनती की शुरुआत सोमवार को यहां हुई जब फिडे के अंतरिम अध्यक्ष विश्वनाथन आनंद और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने ओलंपियाड की मशाल 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता और उज्बेकिस्तान के शीर्ष खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव को सौंपी। शतरंज ओलंपियाड सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिताओं में से एक है जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी 15 से 27 सितंबर तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

शतरंज ओलंपियाड मशाल समारोह की शुरुआत फिडे ने 2022 में ओलंपिक मशाल की तर्ज पर की थी। इसका उद्देश्य खेल की वैश्विक पहुंच का जश्न मनाने के साथ प्रतियोगिता को लेकर उत्साह पैदा करना है। एआईसीएफ के अध्यक्ष नारंग ने कहा, ''शतरंज ओलंपियाड की मशाल इस बात का सशक्त प्रतीक है कि यह खेल देशों और पीढ़ियों को किस तरह जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 में भारत में इस परंपरा की शुरुआत की थी और यह देखना विशेष है कि अब यह लौ भारत से उज्बेकिस्तान जा रही है। भारत शतरंज का जन्मस्थान है और दोनों देशों में शतरंज की गहरी तथा लगातार बढ़ती संस्कृति है।' उन्होंने कहा, ''हम जावोखिर सिंदारोव और उज्बेकिस्तान को शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि समरकंद शतरंज की दुनिया के स्वागत की तैयारी कर रहा है।' भारत ओपन और महिला दोनों वर्गों में गत चैंपियन है और खिताब बरकरार रखने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

टी20: संजू-अभिषेक की तूफानी पारी से भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया, सीरीज पर भारत का कब्जा

नई दिल्ली,हि.स.। भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां अरुण जेटली स्टेडियम में 24,215 दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सात विकेट से हरा दिया। भारत ने 160 रन के लक्ष्य को महज 14.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। ईशान किशन ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने 14.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत की जीत के नायक संजू सैमसन रहे, जिन्होंने महज 22 गेंदों पर चार छक्कों और सात चौकों की मदद से 57 रन की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर चार छक्कों और दो चौकों की मदद से 39 रन बनाए। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 38 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने शुरुआती छह ओवरों में ही 82 रन जोड़कर अफगानिस्तान को दबाव में डाल दिया। सातवें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने राशिद खान की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह सेदीकुल्लाह अटल के हाथों कैच हो गए।

उन्होंने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। हालांकि इसी ओवर में राशिद खान की गेंद पर वह मोहम्मद नबी को कैच दे बैठे। संजू ने 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनका विकेट 99 रन के कुल स्कोर पर गिरा। 11वें ओवर में 123 के कुल स्कोर पर राशिद खान ने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। राशिद की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने स्लिप में श्रेयस अय्यर का शानदार कैच पकड़ा। अय्यर ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों पर नाबाद 40 रन की साझेदारी करते हुए भारत को 14.5 ओवर में सात विकेट की आसान जीत दिला दी।

अफगानिस्तान की ओर से तीनों विकेट राशिद खान ने लिए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही और निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 159 रन ही बना सकी। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर मेडन फेंककर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रहमानुल्लाह गुरबाज़ को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। गुरबाज़ लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं खोल सके। इब्राहिम जादरान ने इसके बाद तेजी से रन बनाए और चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह को दो चौके लगाए। पावरप्ले के छह ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 41 रन था। जादरान और सेदीकुल्लाह अटल ने दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 51 रन जोड़े।

नीतिश कुमार रेड्डी ने नौवें ओवर में जादरान को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। जादरान ने 33 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 37 रन बनाए। इसके बाद 10वें ओवर में रवि बिश्नोई ने सेदीकुल्लाह अटल को तिलक वर्मा के हाथों कैच करा दिया। अटल ने 15 गेंदों पर 12 रन बनाए। नीतिश रेड्डी ने 11वें ओवर में गुलबदीन नैब को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर भारत को चौथी सफलता दिलाई। नैब ने आठ गेंदों पर 10 रन बनाए। अज़मतुल्लाह उमरजई को 12वें ओवर में जीवनदान मिला, जब अक्षर पटेल की गेंद पर रवि बिश्नोई ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। उस समय उमरजई पांच रन पर खेल रहे थे। हालांकि वह इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और 14वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर तिलक वर्मा को कैच देकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने दरविश रसूली को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को छठी सफलता दिलाई। रसूली ने 15 गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके की मदद से 26 रन बनाए। यह मैच में तिलक वर्मा का तीसरा कैच था। इसके बाद राशिद खान और मोहम्मद नबी ने तेजी से रन जुटाए। राशिद ने 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ दो चौके और एक छक्का लगाकर 16 रन बटोरे। राशिद और नबी ने सातवें विकेट के लिए 28 गेंदों पर 48 रन की साझेदारी की। जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में नबी को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। नबी ने 13 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 20 रन बनाए। आखिरी ओवर में नीतिश कुमार रेड्डी ने राशिद खान को अक्षर पटेल के हाथों कैच करा दिया। राशिद ने 16 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन बनाए। नूर अहमद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अफगानिस्तान की पारी का समापन किया। नूर अहमद सात और मुजीब उर रहमान चार रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से नीतिश कुमार रेड्डी ने तीन ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 35 रन देकर दो विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 25 रन, अक्षर पटेल ने चार ओवर में 28 रन और रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 32 रन देकर एक-एक विकेट लिया। नीतिश रेड्डी को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

सिडनी स्वेनी के विज्ञापन पर महिला खिलाड़ियों ने खोला मोर्चा, अपमानजनक करार दिया

लंदन। अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्वेनी के एक विज्ञापन का महिला खिलाड़ियों ने कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए इसे खेलों में महिलाओं को 'सेक्स' के नजरिए से देखना करार दिया। स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म नोविग के विज्ञापन में, स्वेनी बहुत कम या बिना कपड़ों के दिखाई देती हैं। वह इस विज्ञापन में अपने शरीर के कुछ हिस्सों को फुटबॉल और अन्य खेल परिधानों से ढकती हैं। कई महिला खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन की आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया।

चार बार की ओलंपिक तैराकी स्वर्ण पदक विजेता एरियार्ने टिटमस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''इसे देखकर मुझे कितना गुस्सा आ रहा है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हम ऐसी दुनिया में कैसे जी रहे हैं जहां महिलाओं के शरीर का व्यवसाईकरण और महिलाओं के खेल को 'सेक्सुअलाइज़' (कामुकता के रूप में पेश करना) करना अभी भी आम बात है। हंगरी के बुडापेस्ट में अल्टीमेट चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ब्रिटिश स्प्रिंटर एमी हंट ने बीबीसी से साक्षात्कार के दौरान कैमरे की तरफ देखकर सिडनी स्वेनी को संबोधित करते हुए कहा, ''सिडनी स्वेनी, खेल जगत में महिलाएं ऐसी दिखती हैं। मांसपेशियां, कड़ी मेहनत, पसीना, खून, आंसू। अमेरिका की पूर्व जिम्नास्ट ग्रेसी क्रैमर ने इस विज्ञापन को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, ''मैंने अपना पूरा जीवन एक ऐसे खेल में बिताया है जहां महिला खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा 'सेक्सुअलाइज़' किया जाता रहा है।

उन्हें केवल उनके शरीर तक सीमित कर दिया गया है। उन्हें अपनी असल काबिलियत के लिए गंभीरता से लिए जाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया गया है। क्रेमर ने महिला खिलाड़ियों के अभ्यास की तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा, ''खेल जगत में एक महिला ऐसी दिखती है। जर्मन रग्बी खिलाड़ी सोफी फेला ने कहा कि महिला खिलाड़ी लड़कियों और महिलाओं के लिए आदर्श बन सकती हैं क्योंकि वे समाज के सौंदर्य और नारीत्व के आदर्शों से खुद को ''अलग'' करने में सक्षम होती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, ''और इसीलिए सिडनी स्वेनी का वह विज्ञापन दुनिया की हर महिला खिलाड़ी के लिए अपमानजनक है। नोविग ने टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। स्वेनी के जनसंपर्क अधिकारी ने भी टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

पटाया की अंतरराष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में आसनसोल की पंपा पाल ने जीता स्वर्ण

आसनसोल,एजेंसी। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में भारत और पश्चिम बंगाल के प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल की गृहिणी पंपा पाल ने 42 से 50 वर्ष आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता से लौटने के बाद सोमवार को आसनसोल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पंपा पाल ने अपनी उपलब्धि और संघर्ष की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि पटाया में आयोजित इस ओपन इंटरनेशनल योगासन प्रतियोगिता में नौ देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल से कुल 49 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिनमें 19 ने स्वर्ण, 17 ने रजत और नौ प्रतिभागियों ने कांस्य पदक हासिल किया।

पंपा पाल ने बताया कि उनके आयु वर्ग में प्रतियोगिता के दौरान तीन अनिवार्य और दो वैकल्पिक आसन करने थे। वैकल्पिक आसनों में हैंड बैलेंस और लेग बैलेंस शामिल थे। अनिवार्य आसनों की जानकारी आयोजकों की ओर से पहले ही दे दी जाती है और उसी के आधार पर प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि गृहिणी होने के साथ योग को आगे बढ़ाना उनके लिए आसान नहीं है। सुबह करीब चार बजे उठकर घर के कामकाज से दिन की शुरुआत होती है। सुबह चार से छह बजे तक घरेलू काम करने के बाद साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक योग की कक्षाएं चलाती हैं। इसके बाद घर के काम, टिफिन और रसोई की जिम्मेदारी निभाने के बाद दोपहर तीन बजे से फिर योग की कक्षा शुरू हो

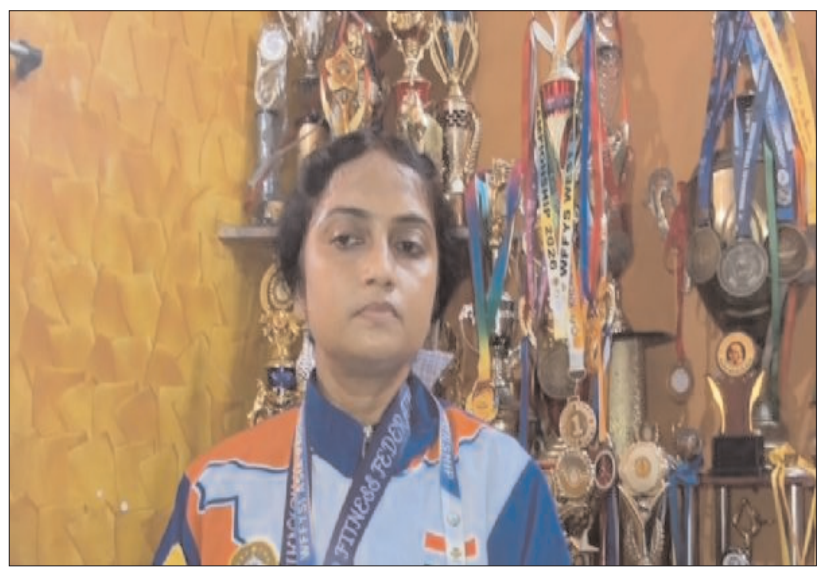

जाती है। योग की ट्यूशन के माध्यम से वह परिवार के खर्च में भी सहयोग करती हैं। उनके पति निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और बेटा पढ़ाई के साथ ऑनलाइन ट्यूशन कर आय में सहयोग करता है। पंपा पाल ने कहा कि वह और उनके जैसी कई प्रतिभाएं जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस दिशा में उचित मूल्यांकन और सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आसन पूरी तरह सही नहीं होने या पैर की स्थिति ठीक नहीं होने जैसी वजहों से प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में वे ओपन इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। पंपा पाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का संदेश है 'खेलो इंडिया, खेलो', लेकिन जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों और योग प्रतिभाओं को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पार करने के बाद कई प्रतिभाएं राज्य स्तर पर ही रुक जाती हैं। सरकार को ऐसी प्रतिभाओं का उचित मूल्यांकन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और भविष्य में योग खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर और सहयोग मिलेगा।

एशियाई खेल 2026: हॉकी में भारत की नजर स्वर्ण पर, लॉस एंजिल्स ओलंपिक का टिकट भी दांव पर

नई दिल्ली,एजेंसी। हाल ही में संपन्न विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम के आठवें और महिला टीम के पांचवें स्थान पर रहने के बाद अब दोनों टीमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी। पुरुष वर्ग में भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जबकि महिला टीम भी चीन को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफिकेशन का रास्ता भी खोलेगा। क्रेग फुल्टन की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम पिछले चार वर्षों से एशियाई हॉकी में अपना दबदबा बनाए हुए है। वर्ष 2023 से भारत ने दो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और एशियाई खेलों सहित सभी महाद्वीपीय प्रतियोगिताएं जीती हैं और इस दौरान उसे एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।

हालांकि, लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतना आसान नहीं होगा। वर्ष 2006 के बाद से कोई भी टीम लगातार दो संस्करणों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण नहीं जीत सकी है। काकामिगाहारा में भारतीय टीम का अभियान एक सप्ताह से भी कम समय में शुरू होगा और विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह प्रतियोगिता फुल्टन और टीम के कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। विश्व कप में अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, जुगराज सिंह, यशदीप सिवाच, संजय राणा और हरमनप्रीत सिंह सहित भारतीय

रक्षापंक्ति के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में 19 गोल खाए, जो विश्व कप में पांचवां सबसे खराब रक्षात्मक रिकॉर्ड था। पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत ने तीन गोल गंवाए। गोलकीपिंग से लेकर फॉरवर्ड लाइन तक लगभग हर विभाग संघर्ष करता नजर आया। हालांकि, पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह की ड्रैगफ्लिक भारत के लिए बड़ी सकारात्मक बात रही। पीठ की समस्या से जूझने के बावजूद उनकी शानदार फिनिशिंग ने कई मौकों पर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। अब हरमनप्रीत की सफलता को फील्ड प्ले में भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना होगा। 2023 के एशियाई खेलों के बाद से अभिषेक नैन लगातार प्रभावी रहे हैं और उन्होंने 86 मैचों में 30 गोल किए हैं। वहीं, अनुभवी फॉरवर्ड मनप्रीत सिंह ने 69 मैचों में 11 गोल किए हैं। फुल्टन ने टीम के चारों क्वार्टर में समान स्तर बनाए रखने में नाकाम रहने पर निराशा जताई थी। हालांकि, एशिया की अन्य टीमों में भी पूरे मैच में लगातार उच्च स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता को लेकर सवाल हैं। लॉस एंजिल्स ओलंपिक का टिकट दांव पर होने के कारण फुल्टन ने टीम में अनुभव को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से आदित्य लालगे की जगह राजकुमार पाल को टीम में शामिल किया गया है, जो विश्व कप में भी टीम के साथ थे।

मैराज का खेल सफर: बल्ले से लेकर बंदूक तक

नई दिल्ली। एक समय था जब मैराज अहमद खान एक बल्लेबाज के रूप में क्रिकेट में नाम कमाने का सपना देखते थे। तीन दशक से अधिक समय बाद 50 वर्षीय मैराज आज भी खेल जगत में नाम कमाने की राह पर हैं, बस अंतर इतना है कि अब उनके हाथ में बल्ले के बजाय बंदूक है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा से लेकर दुनिया भर के निशानेबाजी रेंज तक, मैराज की यात्रा उन्हें उन जगहों पर ले गई है जिनकी उन्होंने खेल की दुनिया में कदम रखते समय कभी कल्पना भी नहीं की थी।

जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में वह घुड़सवार श्रुति वोरा के बाद भारतीय दल के दूसरे सबसे उम्रदराज सदस्य होंगे। वह चौथी बार एशियाई खेलों में भाग ले रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा समय था जब निशानेबाजी से उनका कोई खास नाता नहीं था। मैराज ने कहा, ''जब 1994 में यह सब शुरू हुआ, तब मैं क्रिकेट खेल रहा था।' मैराज बाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज थे, जो आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। उन्होंने 1996 में जामिया मिलिया इस्लामिया में आने से पहले सीके नायडू और वीनू मांकड़ ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय क्रिकेट भी खेला और विज़ी ट्रॉफी में भी भाग लिया। उनके साथियों में युवा वीरेंद्र सहवाग भी शामिल थे। उन्होंने कहा, ''मैं सहवाग के साथ खेला हूं और उनके साथ काफी नेट प्रैक्टिस की है। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ एक मैच खेला था क्योंकि उसी साल वह भारत की तरफ से खेले। क्रिकेट जहां उनके लिए जुनून था वही निशानेबाजी भी उन्हें धीरे-धीरे आकर्षित करने लगी। मैराज के लिए बंदूकें कोई अनजानी चीज नहीं थीं। उनका कहना है कि उनका परिवार जमींदार था और वे हमेशा से ही बंदूक रखते आए थे।

युवावस्था में उन्होंने एयर राइफल और प्वाइंट 22 राइफल शूटिंग में भी हाथ आजमाया था और यहां तक कि बुलंदशहर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने 30 रुपये की पुरस्कार राशि जीती थी। मैराज ने कहा, ''मैंने उस पैसे से क्रिकेट का बल्ला खरीदा था। दिल्ली आने के बाद ही नियति ने उन्हें खेल के एक अलग रास्ते की ओर मोड़ दिया। मैराज अक्सर सप्ताहांत अपने चचेरे भाई के साथ बिताते थे, जो भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन और वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। एक दिन उन्होंने अपने चचेरे भाई को अपनी बंदूक साफ करते हुए देखा। उन्होंने कहा, ''मैंने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मैं भी उनके साथ वहां चला गया। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उससे वह मंत्रमुग्ध हो गए। वहां कई दिग्गज निशानेबाज थे। इसके बाद मैराज का निशानेबाजी के प्रति लगाव बढ़ता गया। अगले कुछ वर्षों तक मैराज ने ट्रैप शूटिंग और स्कीट शूटिंग दोनों में हाथ आजमाया। इसके बाद 1999 में चेन्नई में एक प्रतियोगिता में मैराज का मुकाबला स्कीट शूट-ऑफ में रोंजन सोढ़ी से हुआ, जिन्होंने बाद में डबल ट्रैप में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता और प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया।

एक नजर

अमेरिकी टैरिफ को लेकर ब्राजील और यूएस के बीच सितंबर के आखिर में बातचीत की तैयारी

रियो डी जेनेरो। अमेरिकी टैरिफ को लेकर ब्राजील और अमेरिका के बीच जल्द ही बातचीत होने की संभावना है। ब्राजील के अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक सितंबर के आखिर में हो सकती है। ब्राजील के विकास, उद्योग, व्यापार और सेवाएं मंत्री मार्सियो एलियास रोजा ने सोमवार (स्थानीय समय के अनुसार) कहा कि वह 30 सितंबर से एक अक्टूबर तक अमेरिका में होने वाली जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात कर सकते हैं। रोजा ने पत्रकारों से कहा, 'बातचीत के रास्ते खुले हैं और ब्राजील बातचीत के लिए तैयार है।' उन्होंने कहा कि ब्राजील अपने उद्योगों, कंपनियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा, लेकिन साथ-साथ संवाद भी जारी रखेगा।

यह नई बातचीत अगस्त में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन बातचीत के बाद शुरू हुई चर्चाओं का अगला चरण है। मार्सियो एलियास रोजा ने कहा कि ब्राजील उन एकतरफा टैरिफों का विरोध करता है जिन्हें वह अनुचित मानता है। हालांकि, उसका इरादा अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करने या व्यापार युद्ध शुरू करने का नहीं है। उन्होंने कहा, 'ब्राजील बहुपक्षीय सहयोग, बातचीत और वार्ता में विश्वास रखता है। हम इन सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल अमेरिका ने कुछ ब्राजीली उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। अलग-अलग व्यापारिक जांचों के तहत लागू इन उपायों के कारण कुछ उत्पादों पर कुल टैरिफ दर 37.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ब्राजील के विकास, उद्योग, व्यापार और सेवाएं मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका के इन नए कदमों का असर ब्राजील से अमेरिका जाने वाले करीब 23.1 प्रतिशत निर्यात पर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में ब्राजील का अमेरिका को निर्यात 17.4 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत कम है। साथ ही, ब्राजील के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी घटकर 9.4 प्रतिशत रह गई है, जो 1997 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने थिम्पू में भूटान नरेश से मुलाकात की

थिम्पू। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को थिम्पू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात की। वे हिमालई देश की अपनी तीन दिन की यात्रा पर हैं, जिसके दौरान वे देश के 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के समारोह में भी शामिल होंगे। किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने फेसबुक पर कहा, 'महामहिम राजा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ। महामहिम ने आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जो भूटान की 3 दिन की यात्रा पर हैं। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह यात्रा भारत के चुनाव आयोग और भूटान के चुनाव आयोग के बीच करीबी संस्थागत सहयोग को और मजबूत करेगी और उनके लगातार जारी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान एक मुख्य कार्यक्रम मंगलवार को पारो के जिग्मे सिंग्ये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ में भूटान का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना होगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) मुख्य अतिथि होंगे। बुधवार को ज्ञानेश कुमार थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है कि वह भूटान के वरिष्ठ सिविल सेवकों के साथ भी बातचीत करेंगे। भूटान में भारतीय दूतावास ने बताया कि पिछले महीने राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपनी पत्नी जेटसुन पेमा और भूटान-भारत मैत्री संघ के पदाधिकारियों के साथ इंडिया हाउस में मुलाकात की थी। दूतावास ने 'एक्स' पर कहा, 'थिम्पू, फुएंटशोलिंग, समत्से, गेलेफू, न्गांगलाम और समद्रुप जोंगखर चैप्टर के भूटान-भारत मैत्री संघ के पदाधिकारियों ने आज इंडिया हाउस में मुलाकात की। इस कार्यक्रम में भूटान के राजा और महामहिम आशी डेकी यांगज़ोम भी शामिल हुए। इसमें आगे कहा गया, 'हम भारत और भूटान के बीच अनोखी दोस्ती और संबंधों के तहत लोगों और समुदाय के स्तर पर संबंधों को मजबूत और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।'

लीबिया से 171 सोमाली प्रवासियों को भेजा गया घर, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कराई सुरक्षित वापसी

मोगादिशु। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) द्वारा आयोजित एक विशेष चार्टर उड़ान के जरिए लीबिया में फंसे 171 सोमाली प्रवासी सोमवार को सुरक्षित रूप से अपने देश लौट आए। लौटने वालों में तीन नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, ये प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में कई देशों से होकर गुजरते हुए लीबिया पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें मानव तस्करों के हाथों शोषण, दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की गई।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन सोमालिया के प्रमुख मैनुएल मार्केस परेरा ने कहा कि प्रवासन कभी भी किसी व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक वापसी और पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से सोमाली प्रवासियों को अपने देश में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर मिल रहा है। यूरोपीय संघ (ईयू) के सहयोग से संचालित माइग्रेंट प्रोटेक्शन, रिटर्न एंड रीइंटीग्रेशन इन सब-सहारा अफ्रीका कार्यक्रम के तहत यह चार्टर उड़ान संचालित की गई। उड़ान सबसे पहले उत्तरी सोमालिया के हरगेइसा में उतरी, जहां 42 प्रवासी उतरे। इसके बाद शेष यात्री राजधानी मोगादिशु पहुंचे, जहां अधिकारियों और उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि लौटने वाले कई प्रवासी अपने परिवारों से लंबे समय से बिछड़े हुए थे और उन्हें भोजन, आश्रय तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। ऐसे लोगों को तत्काल मानवीय सहायता और सुरक्षा समर्थन प्रदान किया गया है। संस्था के अनुसार, अगस्त 2022 से अब तक यूरोपीय संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन और सोमाली सरकार की साझेदारी के तहत करीब 2,000 सोमाली प्रवासियों की लीबिया से स्वैच्छिक वापसी कराई जा चुकी है। वर्ष 2026 के अंत तक और भी चार्टर उड़ानों की योजना बनाई गई है।

मेक्सिको के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल मंजूर नहीं: राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबौम

मेक्सिको सिटी,एजेंसी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबौम ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार देश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी दखल या हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध सहयोग और तालमेल पर आधारित होने चाहिए। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेनबौम ने उन लोगों की आलोचना की जो, उनके मुताबिक, विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अमेरिका के कुछ वर्गों और मेक्सिको के विपक्षी दलों में भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, 'हम हमेशा इस सिद्धांत का बचाव करेंगे कि किसी तरह का हस्तक्षेप या दखल नहीं होना चाहिए। सिर्फ सहयोग और समन्वय होना चाहिए और वह भी बिना किसी अधीनता के। यही हमारा रुख रहेगा, क्योंकि यह हमारे सिद्धांतों, हमारे इतिहास, हमारी सोच और हमारे संविधान के अनुरूप है।

सि?हुआ न्यूज के अनुसार, शेनबौम ने एक जनमत सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि 91 प्रतिशत लोगों ने किसी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर किसे फायदा होता है जब यह धारणा फैलाने की कोशिश की जाती है कि मेक्सिको के लोग कुछ और सोचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के कुछ समूह और दक्षिणपंथी मीडिया हस्तक्षेप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस बीच, निजी क्षेत्र के आर्थिक अध्ययन केंद्र (सीईईएसपी) ने सोमवार को कहा कि मेक्सिको सरकार का 2027 के लिए प्रस्तावित आर्थिक पैकेज पहले की तुलना में ज्यादा यथार्थवादी आर्थिक तस्वीर पेश करता है, क्योंकि सरकार ने आर्थिक विकास (ग्रोथ) के अनुमान कम कर दिए हैं। हालांकि, इससे सार्वजनिक कर्ज को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं।

अपने साप्ताहिक आर्थिक विश्लेषण में सीईईएसपी ने कहा कि पिछले सप्ताह संसद (कांग्रेस) में पेश किए गए बजट प्रस्ताव में 2026 और 2027 के विकास अनुमान घटाए गए हैं। इससे ये अनुमान अब वित्तीय विश्लेषकों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आकलनों के ज्यादा करीब आ गए हैं। सीईईएसपी ने कहा, 'मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क के आंकड़ों में किया गया यह बदलाव ज्यादा वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, संगठन ने चेतावनी दी कि बजट में अभी भी कुछ ऐसे अनुमान शामिल हैं जो जरूरत से ज्यादा आशावादी हो सकते हैं। मेक्सिको सरकार कई वर्षों से वित्तीय अनुशासन (फिस्कल कंसॉलिडेशन) की नीति पर काम कर रही है। उसका लक्ष्य धीरे-धीरे बजट घाटा कम करना और सार्वजनिक कर्ज को स्थिर रखना है, ताकि सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार बढ़ते कर्ज पर निर्भरता न बढ़े।

पश्चिमी कैमरून में संदिग्ध अलगाववादी लड़ाकों ने सात लोगों का किया अपहरण, बंधकों को छुड़ाने के लिए अभियान शुरू

याउंडे। कैमरून के पश्चिमी क्षेत्र में संदिग्ध अलगाववादी लड़ाकों ने एक ही परिवार के सात लोगों का अपहरण कर लिया। यह घटना रविवार रात पश्चिमी क्षेत्र के नून डिवीजन स्थित बंगोरैन इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, हथियारबंद हमलावरों ने एक परिवार के घर में घुसकर लोगों को अगवा कर लिया।

क्षेत्र के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अपहृत सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादी उग्रवादी रात में उस समय घर में घुसे जब परिवार के सदस्य सो रहे थे और उन्हें बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए। सुरक्षा बलों ने बंधकों को छुड़ाने और हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह भी स्थानीय लोगों और सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि कैमरून के संघर्षग्रस्त अंग्रेजी भाषी उत्तर-पश्चिम (नॉर्थवेस्ट) और दक्षिण-पश्चिम (साउथवेस्ट) क्षेत्रों में सशस्त्र अलगाववादी समूहों ने एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और कई जगह झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। अलगाववादी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कहा था कि 7 सितंबर से शुरू किया गया यह लॉकडाउन नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को बाधित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र की राजधानी बमेंडा में लोगों ने तनावपूर्ण माहौल की जानकारी दी है। वहां कई स्कूल बंद हैं और लोगों की आवाजाही काफी सीमित हो गई है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि क्षेत्र में गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं, जिससे लोग भयभीत हैं।

सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं और अधिकांश गतिविधियां ठप पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में सशस्त्र अलगाववादी लड़ाकों ने लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने वालों को जान से मारने की धमकी दी है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हालात पर नियंत्रण रखने के लिए दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है और दिन-रात गश्त बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उन्हें सामान्य गतिविधियां जारी रखने की सलाह दी गई है। उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों में वर्ष 2017 से सशस्त्र संघर्ष जारी है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपील, मेल-बैलेट में बदलाव की मंजूरी नहीं

वॉशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (स्थानीय समय के अनुसार) ट्रंप प्रशासन को नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों के लिए मेल बैलेट पर नए और व्यापक नियम लागू करने से रोक दिया। कोर्ट ने उस आपातकालीन अपील को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। यह प्रतिबंध अमेरिकी डाक सेवा के नए नियमों पर लगाया गया था। कोर्ट ने अपने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा, 'सरकार के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि जिला अदालत के शुरुआती आदेश को चुनौती देने के मामले में उसकी जीत की संभावना मजबूत है।

कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन राहत देने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है, वे इस मामले में प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि, इस फैसले से यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है कि डाक सेवा भविष्य के चुनावों में ऐसे नियम लागू कर सकती है या नहीं। लेकिन फिलहाल यह सुनिश्चित हो गया है कि तीन नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनावों में इन नियमों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन्हीं चुनावों में यह तय होगा कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर किसका नियंत्रण रहेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, 2024 में लगभग एक-तिहाई अमेरिकी मतदाताओं ने डाक के जरिए मतदान किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी यह संख्या करीब एक-तिहाई बताई है। डाक सेवा ने अगस्त में ये नियम लागू किए थे। इससे पहले मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

इन नियमों के तहत राज्यों को मतपत्रों के लिफाफों का नया डिजाइन बनाना पड़ता। उन पर चुनावी डाक का लोगों, मशीन से पढ़े जा सकने वाले फीचर और हर मतदाता के लिए अलग विशेष बारकोड लगाना जरूरी होता। साथ ही राज्यों को इन डिजाइनों को संघीय मंजूरी के लिए भेजना पड़ता और मतदाताओं के नाम, पते तथा बारकोड की जानकारी एक नए डाक सेवा पोर्टल पर अपलोड करनी होती। जो डाक सामग्री इन नियमों का पालन नहीं करती, उसे स्वीकार नहीं किया जाता और वापस राज्य के चुनाव अधिकारियों को भेज दिया जाता। चुनाव अधिकारियों का कहना था कि मतदान शुरू होने के इतने करीब इस तरह के बदलाव लागू करना संभव नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन पहले ही मतपत्र भेजना शुरू कर चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एक दर्जन से ज्यादा अन्य राज्य भी सप्ताह के अंत तक मतपत्र भेजने की तैयारी कर रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया में एआई से जुड़े खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली की कमी: इंटेलिजेंस प्रमुख

कैनबरा,एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की साइबर खुफिया एजेंसी के प्रमुख की ओर से चेतावनी दी गई है कि देश को एआई से उत्पन्न खतरों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियाई सिग्नल्स डायरेक्टरेट (एएसडी) की डायरेक्टर-जनरल एबिगेल ब्रैडशॉ ने सोमवार को कैनबरा में एक समिट में कहा कि एआई हमले सरकारों और व्यवसायों की ओर से इस्तेमाल की जा रही पुरानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने संगठनों से एआई को एक सुरक्षात्मक टूल के तौर पर अपनाने का आग्रह किया और कहा कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जोखिमों की पहचान करने के लिए एआई कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब ऑस्ट्रेलियाई राजनेता और एआई कंपनियों के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चेतावनियों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि एआई विकसित करने की दौड़ मानवता की उसे नियंत्रित करने की क्षमता से आगे निकल सकती है। ब्रैडशॉ ने कहा, 'अभी हमारे पास जिस चीज की कमी है (जो साइबर संदर्भ में तो है लेकिन एआई संदर्भ में अभी तक औपचारिक रूप से नहीं है) वह है एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली। कैनबरा में यह समिट एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई की ओर से शनिवार को उद्योग से गति धीमी करने और तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं से सुरक्षा उपायों के प्रति मॉडलों के अनुपालन को सत्यापित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों

बाद आयोजित की गई थी। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एक्सएआई के एलन मस्क की ओर से अमोदेई की बातों से सहमति जताई गई। इसके जवाब में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऑस्ट्रेलियाई सहायक मंत्री एंड्रयू चार्लटन ने सोमवार को कहा कि वह नहीं चाहते कि एआई के लिए सुरक्षा नियम (गाडरील्स) तय करने की पूरी जिम्मेदारी केवल टेक्नोलॉजी कंपनियों या संयुक्त राज्य अमेरिका की हो। एंड्रयू चार्लटन ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात की ज्यादा परवाह करनी चाहिए कि अलग-अलग मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्या कहते हैं या अलग-अलग अधिकारी क्या चाहते हैं। मैं इसे कंपनियों पर छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं और न ही मैं इसे महाशक्तियों पर छोड़ने के पक्ष में हूं।'

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के अमेरिकी प्रस्ता व पर रूस राजी हुआ तो यूक्रेन भी करेगा समर्थन : जेलेंस्की

कीव,एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने एक मजबूत प्रस्ताव दिया कि दोनों पक्ष क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमले रोक दें। उन्हों ने कहा कि अगर रूस अमेरिकी प्रस्ताव पर अमल करता है तो यूक्रेन इस तनाव कम करने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यह अमेरिका की तरफ से एक मजबूत प्रस्ताव है कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) पर होने वाले हमलों को रोक दें। अगर यह तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम बन सकता है, यानी रूस हमारे महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले बंद करे और हम जवाबी हमले रोके, तो यूक्रेन इस तनाव को कम करने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है।'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ऊर्जा ढांचे (एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर हमले नहीं करने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पोस्टल पर साझा की। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस व्यवस्था के पीछे किसने बातचीत कराई या इससे पहले दोनों पक्षों के बीच किस स्तर पर वार्ता हुई। ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध को दुनिया में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह बताया। उन्होंने लिखा, 'दुनिया में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण रूस-यूक्रेन युद्ध है, ईरान नहीं। जेलेंस्की ने अपने पोस्टा में कहा, 'हम देख रहे हैं कि रूस हमारी सटीक कार्रवाइयों की वजह से अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव महसूस कर रहा है। अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस वास्तव में युद्ध खत्म करने की ईमानदार इच्छा रखता है। अगर हमारे अमेरिकी साझेदार यह सुनिश्चित कर सकें कि रूस सच में इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है और लंबे समय के लिए ऐसा करना चाहता है, तो यूक्रेन भी तनाव कम करने के लिए अपने कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि शांति की जरूरत है। ऊर्जा व्यवस्था, खाद्य आपूर्ति के रास्ते और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, इन सभी मुद्दों को हमलों को खत्म करने और युद्ध समाप्त करने की बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। हमें एक मजबूत और न्यायसंगत समाधान चाहिए, जो सिर्फ 'चुनावों' तक सीमित न हो, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ साबित हो। हम अपने साझेदारों से इस बारे में ठोस और स्पष्ट जानकारी की उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन नेटवर्क और अन्य ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने भी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों के कारण बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की पुष्टि की है।

मॉस्को के साथ 'संयुक्त सहयोग' बढ़ाएगा उत्तर कोरिया, किम जोंग ने रूस से संबंध मजबूत करने का किया वादा

सोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजे एक संदेश में कहा है कि उनका देश मॉस्को के साथ 'संयुक्त सहयोग' को और बढ़ाएगा तथा उसे और गहरा करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के अनुसार, किम जोंग-उन ने 9 सितंबर को उत्तर कोरिया की स्थापना की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन की ओर से भेजे गए बधाई संदेश के जवाब में उन्हें धन्यवाद दिया।

पत्र में कहा गया कि उत्तर कोरिया की इच्छा पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत है कि वह रूस के साथ अपने संयुक्त सहयोग को हर क्षेत्र में और आगे बढ़ाए। यह सहयोग दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती, पड़ोसी संबंधों, आपसी मदद और मजबूत गठबंधन पर आधारित है। हालांकि किम ने यह साफ नहीं किया कि 'संयुक्त सहयोग' से उनका क्या मतलब है, लेकिन माना जा रहा है कि यह उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक सहयोग की ओर इशारा करता है। केसीएनए के अनुसार, किम ने कहा कि दोनों देश कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भी अपने गठबंधन के इतिहास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को अपना अटल समर्थन जारी रखने का भी भरोसा दिया। जून 2024 में राष्ट्रपति पुतिन की प्योंगयांग यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश बिना देरी के सैन्य सहायता प्रदान करेगा। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया पहले ही हजारों सैनिक और पारंपरिक हथियार भेज चुका है। इसी बीच, इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया और रूस ने तुमेन नदी पर बने एक नए सड़क पुल को भी खोल दिया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इसे दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को 'नई ऊर्जा' देने वाला महत्वपूर्ण ढांचा बताया। पुल के उद्घाटन समारोह का आयोजन उत्तर कोरिया के रासोन और रूस के खासन में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री पाकथे-सोंग और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस पुल का निर्माण अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था। इसकी योजना जून 2024 में प्योंगयांग में हुई किम जोंग-उन और व्लादिमीर पुतिन की शिखर बैठक के बाद बनाई गई थी। केसीएनए के मुताबिक, यह पुल विभिन्न प्रकार के वाहनों और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, लोगों के आदान-प्रदान, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

एक नजर

गुजरात में 95 तहसीलों में बारिश, कच्छ की मांडवी में सबसे ज्यादा 6.97 इंच, सौराष्ट्र में भी अलर्ट

गांधीनगर,एजेंसी। गुजरात में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है और कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। खासकर कच्छ जिले में आज सुबह से ही बारिश ने जोरदार दस्तक दी। कच्छ की मांडवी तहसील में सुबह 8 से 10 बजे के बीच महज दो घंटे में 5 इंच से अधिक बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई थी। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, गांधीनगर के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य की 95 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें कच्छ की मांडवी तहसील में सबसे अधिक 6.97 इंच बारिश हुई। इसके अलावा अबडासा में 2.13 इंच, मुंद्रा में 1.57 इंच, नखत्राणा में 1.30 इंच और भुज में 1.26 इंच बारिश दर्ज की गई। देवभूमि द्वारका की खंभालिया तहसील में 0.87 इंच, ओखा मंडल में 0.79 इंच, सिहोर में 0.71 इंच और नडियाद में 0.63 इंच बारिश हुई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 से 10 बजे के दौरान राज्य की 25 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कच्छ की मांडवी में 5 इंच से अधिक बारिश हुई। मुंद्रा में 0.79 इंच, भुज में 0.59 इंच, नखत्राणा में 0.39 इंच, लखपत में 0.35 इंच, गांधीधाम में 0.24 इंच और अंजार में 0.20 इंच बारिश दर्ज की गई। कच्छ के अलावा पोरबंदर, ओखा मंडल, सूरत शहर, कोडिनार, जामनगर, राणावाव, जाफराबाद और गिर सोमनाथ समेत कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बनी हुई है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में 579.23 करोड़ रूपये की राशि ट्रांसफर की

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प सभागार में आयोजित आनुग्रहिक राहत वितरण कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रभावित 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों के बैंक खातों में 7 हजार रूपये प्रति परिवार के दर से 579.23 करोड़ रूपये की आनुग्रहिक राहत राशि का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 15 जिले, 88 प्रखण्ड, 575 ग्राम पंचायत एवं 2,642 गांव तथा 21 शहरों के 136 वार्ड के लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 55 हजार हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुँचा है। प्रभावित क्षेत्रों में हर स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1,200 से अधिक सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इन सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से अब तक लगभग 1.28 करोड़ थालियां परोसी जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन, पेयजल, दवा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जाएं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक राहत एवं सहायता सुविधाएं निरंतर जारी रहेंगी। प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 7 हजार रूपये की दर से 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों के बैंक खातों में छ्क्क्ष के माध्यम से कुल 579.23 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गयी है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतें। यदि कोई पात्र प्रभावित परिवार सहायता से छूट गया है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर राहत सूची में शामिल करें। कोई भी पात्र प्रभावित परिवार सरकारी राहत से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कि राहत कार्यों के साथ-साथ पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण का कार्य भी तेज गति से करें। राज्य में ' पहले से बेहतर पुनर्निर्माण की थीम पर कार्य करें। एक माह के भीतर सभी पुनर्प्राप्ति कार्य पूरे किए जाएं। इसमें कृषि इनपुट सब्सिडी (कृषि निवेश अनुदान), सड़कों की मरम्मती सहित प्रभावित परिवारों एवं किसानों को सभी आवश्यक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए तथा प्रभावित परिवारों, किसानों और अन्य संबंधित लोगों को नियमानुसार शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर बाढ़ से हुई क्षति का समुचित एवं तथ्यपरक आकलन कर रिपोर्ट तैयार रखें। प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति का दस्तावेजीकरण करते हुए आवश्यक सहायता एवं पुनर्प्राप्ति कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ायें। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा, सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

एनसीआर में लगेंगे 775 एएनपीआर कैमरे: अनिल विज

चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में एनसीआर के प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 एएनपीआर कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 41 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

परिवहन मंत्री ने मंगलवार को बताया कि जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों की पहचान तथा पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों के एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से ऐसे पुराने वाहनों की प्रभावी पहचान की जा सकेगी और निर्धारित पर्यावरणीय प्रावधानों को लागू करने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में 249, सोनीपत में 215, झज्जर में 195 तथा फरीदाबाद में 116 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इस प्रकार इन चार जिलों में कुल 775 कैमरे स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल लगभग 2,780 एएनपीआर कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता है।

इनमें से प्रथम चरण में एनसीआर के इन चार प्रमुख जिलों में 775 कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। विज ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार एएनपीआर कैमरों की स्थापना का कार्य 30 सितंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है।

इसके पश्चात एक अक्टूबर, 2026 से हरियाणा में पंजीकृत जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जानी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एएनपीआर तकनीक के माध्यम से जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों की पहचान को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है। उन्होंने कहा कि एएनपीआर कैमरों के माध्यम से पुराने वाहनों की पहचान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन और एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने रेणुका जी में किया पांच सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के पहले बैच के तहत पांच सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 28.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएमजीएसवाई-4 के तहत बनने वाली इन पांच सड़कों में बिरला-गाटू से मढारा, कटवारी बगराथ से बिरला, ठाकर से कुज्जेवाला, गांव बखान से केलेवाला और खरकोली से उंग्गर कांडो सड़क शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को इन परियोजनाओं के लिए बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण आधार हैं। राज्य सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से स्थानीय

लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को पांच सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क ढांचे को मजबूत करने और मौजूदा सड़कों में सुधार को प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले और प्रदेश के अन्य हिस्सों में इन परियोजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने के लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला शक्ति पॉलीटार्प का पब्लिक इश्यू, 22 सितंबर को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली,एजेंसी। प्लास्टिक तिरपाल और पैकेजिंग फैब्रिक बनाने वाली कंपनी शक्ति पॉलीटार्प का 26.93 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 17 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 18 सितंबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 21 सितंबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 22 सितंबर को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद पहले दिन इस आईपीओ को 64 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल चुका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 56 रुपये प्रति शेयर से लेकर 59 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,36,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 45.64 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 30.37 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 34.62 प्रतिशत हिस्सा हिस्सा रिजर्व है। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 29.97 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.04 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए नेक्सजेन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है। शक्ति पॉलीटार्प की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 98 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 4.97 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 10.06 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 62.23 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 166.50 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 216.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 23.26 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 48 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ बड़ी उछाल के साथ 72.51 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

'यूपी राइज 2026': इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज से जॉब क्रिएटर बनेंगे आगरा के युवा

आगरा,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'आत्मनिर्भर यूपी' विजन को धरातल पर उतारने के लिए मंगलवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित जेपी सभागार में 'यूपी राइज 2026' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. आशु रानी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक आत्रेय मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस आयोजन में शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए 1000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं की मानसिकता में बदलाव लाकर उन्हें केवल नौकरी तलाशने वाला न बनाकर, स्वयं का उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने वाला 'जॉब क्रिएटर' (रोजगार सृजक) बनाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में नवाचार (इनोवेशन) और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए निरंतर और धरातलीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम में युवाओं को राज्य सरकार की विभिन्न रोजगारपरक नीतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यूपी स्टार्टअप फंड, मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना और यूपी स्किल मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना, फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना और महिला सामर्थ्य योजना से जुड़ी नीतियों के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता व आसान सब्सिडी के बारे में भी बताया गया, ताकि युवा बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने स्टार्टअप को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल सकें। यूपी राइज की थीम के अनुरूप, आगरा के युवाओं ने अपनी उद्यमशीलता का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन में कुल 30 स्टार्टअप आइडिया आए, जिनमें से 11 बेहतरीन आइडिया को शॉर्टलिस्ट किया गया।

इनमें कलाकारों के लिए एआई आधारित मार्केटप्लेस 'Kalaverse', कंस्ट्रक्शन प्लानिंग को आसान बनाने वाला 'Build Easy AI', अनदेखे पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने वाला 'Hidden India' और बेकरी के लिए 'Organic floral cream color' जैसे आइडियाज शामिल रहे। वहीं, ई-रिक्शा चालकों की बैटरी समस्या सुलझाने के लिए Saathi EV, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाला 'The Craft Duo' और मंदिर के कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाने वाले 'Temple 2 Green' जैसे अनूठे पर्यावरण-अनुकूल प्रोजेक्ट्स ने भी खूब वाहवाही लूटी। जूरी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने बेहतरीन प्रेजेंटेशन देकर 'Re-Oil' (इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस) ने प्रथम स्थान हासिल कर 25,000 रुपये का मुख्य पुरस्कार जीता। वहीं, छात्रों की पढ़ाई को व्यवस्थित करने वाले 'Study App' और सोलर पैनल की सफाई के लिए रोबोटिक ब्रश तकनीक वाले 'Solar Sweep' की टीम संयुक्त रूप से रनरअप रही। छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए जाने-माने कॉर्पोरेट विशेषज्ञ हर्षित देसाई, कपिल त्रिमाल और विवेक गोयल बतौर मेंटर मौजूद रहे। गौरतलब है कि यूपी राइज कार्यक्रम प्रदेश के 25 शहरों के 30 प्रमुख कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। इसका अगला पड़ाव 18 सितम्बर 2026 को मथुरा स्थित जीएलए विश्वविद्यालय में होगा।

गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए झारखंड बना देश का पहला मॉडल राज्य, केंद्र ने इंटीग्रेटेड एनसीडी मॉडल को दी हरी झंडी

रांची,एजेंसी। गैर-संचारी रोगों यानी नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज (एनसीडी) की रोकथाम और समग्र प्रबंधन के लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए इंटीग्रेटेड एनसीडी मॉडल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने झारखंड को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए देश का पहला मॉडल राज्य चुना है। 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-1 में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और मिशन डायरेक्टर, आराधना पटनायक ने इस मॉडल को मंजूरी दी, जिससे झारखंड में इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया। मॉडल के सफल मूल्यांकन के बाद इसे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इंटीग्रेटेड एनसीडी मॉडल को झारखंड में मिशन मोड पर लागू करने के लिए जल्द ही एक भव्य स्टेट लेवल वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और सभी संबंधित हितधारकों को एक मंच पर लाया जाएगा। गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण को सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कार्यशाला में विभागीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति का भी प्रस्ताव रखा गया है। इससे अभियान को

उच्चस्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन मिलने की उम्मीद है।

इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में सघन अभियान चलाना है। इसके तहत कैंसर के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य घटकों को एक साझा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसके तहत उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच व उपचार, हृदय रोगों की रोकथाम और प्रबंधन, तंबाकू नियंत्रण, मुख स्वास्थ्य, पैलिएटिव केयर (एक विशेष प्रकार की चिकित्सा सेवा), मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्तर पर शुरुआती स्क्रीनिंग, समय पर रोग की पहचान और डिजिटल ट्रैकिंग, मरीजों को लगातार उपचार और देखभाल उपलब्ध कराना शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इस जनस्वास्थ्य अभियान को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड ने राज्य में कार्यरत विकास भागीदारों, नागरिक समाज संगठनों और प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को सहयोग का खुला आमंत्रण दिया है। तकनीकी विशेषज्ञता, सामुदायिक कार्यबल और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के माध्यम से सहयोग करने वाली संस्थाएं इस एकीकृत ढांचे से सीधे जुड़ सकेंगी। उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव एवं मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने की। झारखंड की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक शशि प्रकाश झा, राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. रवि राज और राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अनिमा किस्कू ने राज्य की प्राथमिकताओं और कार्ययोजना की जानकारी साझा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एनसीडी प्रभाग के उप-महानिदेशक एवं निदेशक ईएमआर डॉ. एल. स्वास्तिचरण ने झारखंड के इंटीग्रेटेड मॉडल का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

झारखंड चेंबर के सत्र 2026-27 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गठन, तुलसी पटेल बने अध्यक्ष

रांची। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर एवं पवन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। चुनाव पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स के हित में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

बैठक में सत्र 2026-27 के पदाधिकारियों का चयन किया गया। सर्वसम्मति से तुलसी पटेल को झारखंड चेंबर का अध्यक्ष चुना गया। वहीं विकास विजयवर्गीय और रोहित पोद्दार को उपाध्यक्ष, रोहित अग्रवाल को महासचिव, अमित शर्मा और पूजा ढाढा को सह सचिव एवं नवजोत अलंग को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल ने चुनाव के दौरान राज्य के व्यापार और उद्योग जगत से मिले सहयोग और समर्थन के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चेंबर को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए सभी सदस्यों, व्यापारियों एवं उद्यमियों के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने झारखंड चेंबर के स्थापना दिवस के अवसर पर चेंबर के संस्थापक अध्यक्ष राय बहादुर हरक चंद जैन और संस्थापक सचिव एआर बुधिया के प्रति श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त किया। उन्हों ने कहा कि उनके प्रयासों और दूरदृष्टि से स्थापित यह संस्था आज राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों की एक सशक्त आवाज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संस्थापकों की इसी सोच, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाते हुए चेंबर को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाते हुए सरकार और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से इस उद्देश्य में सक्रिय सहयोग की अपील की। बैठक के बाद चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर और पवन शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदभार सौंपा। साथ ही उन्होंने चेंबर के स्थापना दिवस पर सभी चेंबर के सदस्यों को बधाई दी।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)